घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 93- सोमवार 02- फरवरी 2026,पृष्ठ - 8+4 मूल्य 4 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया केंद्रीय बजट...

सरकार विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगी : निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली,01 फरवरी 2026। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को अंपनी मंजूरी दी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा,सरकार 'विकसित भारत' की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगा। भारत वैश्विक बाजार के साथ गहनता से जुड़ा रहेगा। मैं पार्ट-ए की शुरुआत करते हुए इस देश के नागरिकों का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया है। सीतारमण ने कहा कि हमने सुनिश्चित किया है कि किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों, युवाओं,महिलाओं,गरीबों को लाभ मिलता रहे। यह युवा शक्ति से प्रेरित बजट है। हमारी सरकार का संकल्प गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में यह बजट बना है। पहला कर्तव्य है-आर्थिक विकास को सतत तरीके से बढ़ाना। दूसरा कर्तव्य है-जनआकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य है- सबका साथ, सबका विकास। यह सुनिश्चित करना कि सभी को संसाधनों,सुविधाओं और अवसरों तक समान रूप से पहुंच मिले। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करने से पहले रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलीं। राष्ट्रपति मुर्मु ने वित्त मंत्री सीतारमण को दही-चीनी खिलाई। उन्होंने बजट के लिए वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी। बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। यह वित्त वर्ष 2026 के 11.2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में लगभग 9% अधिक है।

एक अप्रैल से लागू होगा आयकर अधिनियम 2025

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर अधिनियम 2025 को 01 अप्रैल से लागू किया जाएगा और इसके नियम तथा 'टैक्स रिटर्न'फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। हालांकि,केंद्रीय बजट में स्टैंडर्ड डिक्डशन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो जाएगा,जो छह दशक पुराने कर कानून का स्थान लेगा। बजट 2026-27 में कर कानूनों में किए गए बदलावों को इस नए कानून में शामिल किया जाएगा। नए आयकर कानून में वित्त वर्ष और आकलन वर्ष की जगह अब नया टर्म 'कर वर्ष'का इस्तेमाल किया जाएगा। सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा,''इसे (प्रत्यक्ष कर संहिता) रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। आयकर अधिनियम, 2025 पहली अप्रैल,2026 से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि सरलीकृत आयकर नियमों और फॉर्म को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा, जिससे करदाताओं को इसकी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।'' वित्त मंत्री ने छात्रों,तकनीकी पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई जैसे छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पहले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए जुर्माने की राशि पर करदाताओं पर कोई ब्याज नहीं देना होगा,चाहे परिणाम कुछ भी हो। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर से 31 मार्च करने का प्रस्ताव किया। मामूली शुल्क के भुगतान के साथ आयकरदाता इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

केंद्रीय बजट में ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद रक्षा क्षेत्र के लिए 15 फीसदी आवंटन बढ़ा

ऑपरेशन 'सिंदूर' में पिछले साल पाकिस्तान के साथ हवाई संघर्ष के बाद भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 15 फीसदी आवंटन बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने रविवार को केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये दिए, जो पिछले वित्त वर्ष में दिए गए 6.81 लाख करोड़ रुपये से 15 फीसदी ज्यादा है। इससे सेनाओं के आधुनिकीकरण पर सरकार के लगातार ध्यान देने का संकेत मिलता है। हालांकि,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कोई खास नीति की घोषणा नहीं की,लेकिन केंद्र ने रविवार को रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की,जिससे मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कुल रक्षा बजट पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 15 फीसदी की बढ़ोतरी है। पिछले बजट में केंद्र ने डिफेंस के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपये रखे थे, जिससे यह कुल सरकारी खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। पिछले बजट में डिफेंस सर्विसेज (रेवेन्यू) में सैलरी,अलाउंस,मेंटेनेंस और ऑपरेशनल तैयारी का हिस्सा 3.12 लाख करोड़ रुपये था।

कैंसर की दवाइयां सस्ती...17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म

सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा,7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं।

माइक्रोवेव ओवन सस्ते...पुर्जों पर ड्यूटी घटी,घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतों में कमी आ सकती है।

बजट प्रतिक्रिया

बजट से किसानों,गरीबों और राज्यों के लिए कोई राहत नहीं : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय बजट 2026-27 को बिना नीति एवं दृष्टि वाला करार देते हुए निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नया विचार नहीं बचा है और यह बजट देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का कोई समाधान नहीं देता। खरगे ने एक्स पोस्ट में कहा कि मिशन मोड अब 'चैलेंज रूट' बन गया है और रिफॉर्म एक्सप्रेस शायद ही कभी किसी 'रिफॉर्म' जंक्शन पर रुकती है। नतीजा यह है कि सरकार के पास न कोई नीति दृष्टि है और न ही राजनीतिक इच्छाशक्ति। किसान अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं, असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई राहत नहीं दी गई है।

रक्षा बजट बढ़ने से भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी : राजनाथ सिंह

लोकसभा में रविवार को पेश केंद्रीय बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सेनाओं के आधुनिकीकरण और सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी को केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया है। केंद्रीय बजट पर रक्षा सचिव ने इस साल के बजट के हिस्से के तौर पर रक्षा क्षेत्र को आवंटित बजट पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय का कुल बजट 7.85 लाख करोड़ होगा, जो पिछले साल के आवंटन से 15 फीसदी ज्यादा है। इससे भी जरूरी बात यह है कि पूंजीगत व्यय में कुल पूंजीगत व्यय परिव्यय 21 फीसदी बढ़कर लगभग 2.9 लाख करोड़ हो गया है।

बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार बजट प्रस्तुत किए जाने को नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज जिस 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार है, इस बजट से उसे नई रफ्तार मिलेगी। पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स देश के साहसी, प्रतिभाशाली और आकांक्षाओं से भरे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है बल्कि वह जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। 140 करोड़ नागरिकों का संकल्प है कि भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बने। उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदार और विश्वसनीय गुणवत्ता आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की वैश्विक भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में हुए बड़े-बड़े ट्रेड डील्स का अधिकतम लाभ देश के युवाओं,छोटे और मध्यम उद्योगों को मिले। इसके लिए बजट में अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया गया है। मोदी ने कहा कि इस बजट में सनराइज सेक्टर्स को अभूतपूर्व समर्थन दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देशभर में वॉटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर,टियर टू और टियर थ्री शहरों के विकास तथा शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा देने जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। सरकार ने बीते वर्षों में स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी पर लगातार निवेश किया है। उन्होंने टूरिज्म, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने, राज्यों को सशक्त बनाकर बैलेंस्ड डेवलपमेंट सुनिश्चित करने और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए आधुनिक इकोसिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और यह एक सफल अभियान है।

करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल

देश में 789 जिले हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। गर्ल स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान,प्रौद्योगिकी,इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम

लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए शी-मार्ट (शी-मार्ट) बनाए जाएंगे। इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे। यहां महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार पर मालिकाना हक मिलेगा।

दिव्यांगजनों के लिए 'कौशल' और 'सहारा' योजनाओं की घोषणा

केंद्र सरकार ने 2026-27 बजट में दिव्यांगजनों के लिए 'कौशल' और 'सहारा' योजनाओं की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में 'सबका साथ,सबका विकास' के संकल्प को दोहराते हुए दिव्यांगजनों के लिए 'दिव्यांग कौशल योजना' और 'दिव्यांग सहारा योजना' की घोषणा की,ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सरकार का लक्ष्य देश के प्रत्येक वर्ग संसाधनों और सुविधाओं तक समान पहुंच प्राप्त कराना,दिव्यांग कौशल और सहारा योजनाएं दिव्यांगजनों को सार्थक भागीदारी और सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करना है। दिव्यांग कौशल योजना के तहत दिव्यांगजनों को केवल पारंपरिक कार्यों तक सीमित न रखकर उन्हें भविष्य के उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाएगा। इससे वे आईटी,एवीजीसी(एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स),हॉस्पिटैलिटी और खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे क्षेत्रों में रोजगार पा सकें।

एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी से छूट का प्रस्ताव

सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत शिक्षा और मेडिकल मकसद से टीसीएस दर को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने का प्रस्ताव है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले कर्ज का अनुपात जीडीपी का 55.6 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर दी गई बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स तक बढ़ाने का

देश में खोले जायेंगे 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी अहम घोषणाएं की हैं। जिसके तहत देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे। अभी इनकी जगह नहीं बताई गई है। इसके साथ बेहतर मानसिक स्वास्थ्य इलाज के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने निमहंस 2.0 स्थापना की घोषणा की जो देश के लिए प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के तौर पर काम करेगा। इसके साथ ही उत्तर भारत में दो मानसिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। निर्मला सीतारमण ने भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद की योजना का प्रस्ताव रखा।

बैटरी और सोलर पैनल सस्ते...

एनर्जी ट्रांजेक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों (कॅपिटल गुड्स) पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं, सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले 'सोडियम एंटीमोनेट' पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा।

रेल-जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर

7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शहरों के बीच विकास सेतु बनेंगे। मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी में ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

'बायो-फार्मा शक्ति' और हेल्थकेयर

भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 'बायो-फार्मा शक्ति' कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के तहत 3 नए राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही, दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की सफलता के बाद अब 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' लॉन्च किया जाएगा,जो इक्विपमेंट,मटीरियल्स और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर केंद्रित होगा।

हैंडलूम कारीगरों की मदद

नेशनल फाइबर स्कीम बनेगी नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद देने की तैयारी है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड का सिस्टम तैयार किया जाएगा। खादी को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर बनेगी उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति। 2047 तक 10 फीसदी की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाया जाएगा।

संपादकीय

बड़े और ठोस सुधारों का इंतजार

कायम रहना चाहिए रिफॉर्म का सिलसिला...

आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि को रेखांकित किया, लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य हेतु व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। निजी क्षेत्र को 7 प्रतिशत से अधिक विकास दर बनाए रखने के लिए मुख्य इंजन बताया गया,जिसे विनिर्माण और अनुसंधान में निवेश करना होगा। राज्य सरकारों की सक्रियता,नौकरशाही में सुधार,शहरी ढांचे का विकास और कृषि उत्पादकता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण बताया गया है...

संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने यह रेखांकित किया कि तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, लेकिन यदि विकसित भारत के लक्ष्य को सचमुच पाना है तो इन चुनौतियों से पार पाना होगा और चुनौतियों से पार तभी पाया जा सकता है,जब आमूलचूल सुधार किए जाएंगे और उन पर तेजी से अमल भी किया जाएगा।

यह ठीक है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट से रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति मिलेगी,लेकिन देखना यह है कि सभी आवश्यक सुधार हो पाते हैं या नहीं? क्या यह उम्मीद की जाए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में व्यापक सुधारों की घोषणा करेंगी। वास्तव में केवल बजट में ही कुछ बड़े और बुनियादी सुधारों की घोषणा नहीं की जानी चाहिए,बल्कि सुधारों का सिलसिला कायम रहना चाहिए। इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि आर्थिक विकास को केवल सरकारी प्रयासों से गति नहीं दी जा सकती। आर्थिक सर्वेक्षण साफ तौर पर यह कह रहा है कि विकास को अपेक्षित गति देने के लिए निजी क्षेत्र को अपनी सक्रियता दिखानी होगी। विश्व भर में आर्थिक मोर्चे पर जैसी उथल-पुथल हो रही है और अनिश्चितता का जैसा वातावरण है,उसमें सरकार और निजी क्षेत्र को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। निजी क्षेत्र उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसते हुए नहीं दिख रहा है,जो अर्थव्यवस्था के समक्ष आ खड़ी हुई हैं। जब आर्थिक समीक्षा यह स्पष्ट करती है कि निजी क्षेत्र अब केवल एक भागीदार नहीं है,बल्कि 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर को बनाए रखने के लिए मुख्य इंजन है,तब उसे इसी भूमिका में आना होगा और देश को मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाने के साथ शोध एवं विकास में निवेश करना होगा। उसे तकनीक संचालित अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ना होगा और उत्पादकता के मामले में भी सुधार करना होगा। इससे ही हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय बनेंगे और उनकी विश्व में मांग बढ़ेगी। आज ऐसा नहीं है और इसी कारण आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि कई आयात अवांछनीय हैं।

यह भी स्पष्ट है कि अभी देश में उच्चतम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस पर गौर किया जाए कि आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि दोयम दर्जे की गुणवत्ता की वस्तुएं बनाने वालों को संरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। यदि वे प्रतिस्पर्धी नहीं बनते तो उन्हें संरक्षण देना समस्या को बढ़ाना ही है। आज जब स्वदेशी की बातें हो रही हैं, तब उस सामग्री के आयात का कोई औचित्य नहीं,जिसे देश में निर्मित किया जा सकता है।

रिश्ते,शर्तें और डर से घिरी एक पीढ़ी

डॉ.प्रियंका सौरभ
आर्यनगर हिसार हरियाणा

आज के समय में यदि कोई सबसे जोखिम भरा सामाजिक कार्य है, तो वह है–किसी को रिश्ते की बात कहना। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं,बल्कि हमारे बदलते सामाजिक मानस की सच्चाई है। जिस विषय को कभी परिवार,भरोसे और सामूहिक निर्णय का आधार माना जाता था,वह आज शर्तों,अपेक्षाओं और भय की प्रयोगशाला बन चुका है। परिणाम यह है कि अच्छे-खासे घरों में पढ़े-लिखे,सक्षम युवा कुंवारे बैठे-बैठे अधेड़ हो रहे हैं,लेकिन समझौते को कमजोरी मानकर ठुकराया जा रहा है।

आज रिश्ते भावनात्मक समझ से अधिक तकनीकी परियोजना की तरह देखे जा रहे हैं। हर प्रस्ताव एक लंबी चेकलिस्ट के साथ आता है–हाइट कितनी है,रंग कैसा है,पैकेज कितना है, घर कितना बड़ा है,ज़मीन कितनी है, माता-पिता कितने हस्तक्षेप करते हैं, भविष्य में कौन कितना एडजस्ट करेगा। इस गणित में मनुष्य ग़ायब है,आंकड़े उपस्थित हैं। यही वजह है कि रिश्ता तय करने में महीनों लगते हैं,पर टूटने में कुछ हफ्ते भी पर्याप्त हो जाते हैं।

यह पीढ़ी सुविधाओं की भाषा में रिश्ते तलाश रही है। लड़कियों को ऐसा घर चाहिए जहाँ घरेलू श्रम की कोई अपेक्षा न हो,जहाँ जिम्मेदारी का बोझ पुरानी सोच मान लिया जाए। वहीं लड़कों को ऐसी बहू चाहिए जो आधुनिक भी हो और परंपरागत अपेक्षाओं का निर्वाह भी बिना सवाल किए करे। दोनों पक्ष चाहते हैं कि सामने वाला समझौता करे,पर स्वयं झुकने को कोई तैयार नहीं। रिश्ते साझेदारी नहीं, सेवाओं की सूची बनते जा रहे हैं।

हनीमून पेरिस में मनाने का सपना है, लेकिन अपने ही देश और अपने परिवेश की जिम्मेदारियों से बचने में पसीना छूट जाता है। यह विरोधाभास केवल भौगोलिक नहीं,मानसिक है। वैश्विक आकांक्षाएँ हैं,पर स्थानीय दायित्वों से परहेज़। आधुनिकता का अर्थ सुविधाओं का उपभोग समझ लिया गया है,दायित्वों को स्वीकार करना नहीं।

खेती किसी को करनी नहीं,पर ज़मीन–किल्ले–ज़रूर होने चाहिए। मेहनत का सम्मान घटा है,संपत्ति का आकर्षण बढ़ा है। जिस समाज की जड़ें श्रम में थीं,वहाँ अब श्रम से दूरी और संपत्ति से निकटता प्रतिष्ठा का मानक बन गई है। रिश्ता तय करते समय परिश्रम,धैर्य,संघर्ष और जीवन-कौशल की जगह संपत्ति,पद और प्रोफ़ाइल ने ले ली है। इंसान का मूल्यांकन उसके चरित्र से नहीं,उसके संसाधनों से किया जा रहा है।

आज एक-एक इंच हाइट नापी जाती है,रंग,जाति,सैलरी,कार और सोशल मीडिया की मौजूदगी तक गिनी जाती है। विवाह-पूर्व जाँच एजेंसियों की तरह रिश्तों की पड़ताल होती है। लेकिन तमाम जाँच-पड़ताल के बावजूद छह महीने बाद वही लोग कोर्ट के बाहर खड़े

मिल जाते हैं। सवाल यह नहीं कि तलाक क्यों बढ़ रहे हैं,सवाल यह है कि इतनी सावधानी के बाद भी रिश्ते टिक क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमने मानवीय गुणों को मापना छोड़ दिया है–संवाद, सहनशीलता,धैर्य,असहमति में सम्मान और संकट में साथ निभाने की क्षमता। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे त्रासद स्थिति माँ-बाप की है। वे बच्चों से डरते हैं– कि कहीं कुछ कह न दें,कहीं दबाव न डाल दें,कहीं इमोशनल ब्लैकमेल का आरोप न लग जाए। दूसरी ओर बच्चे शादी से डरते हैं–जिम्मेदारी,स्थायित्व और समझौते से। रिश्ता दोनों के बीच पिस रहा है। यह डर का ऐसा चक्र है जिसमें कोई नेतृत्व नहीं चाहता,सब दर्शक बने रहना चाहते हैं।

माता-पिता आज निर्णयकर्ता नहीं, केवल वित्तीय और भावनात्मक सहायक बनकर रह गए हैं। वे न रिश्ता सुझा सकते हैं,न आपत्ति जता सकते हैं। वहीं युवा पीढ़ी स्वतंत्रता चाहती है, लेकिन निर्णयों की जवाबदेही से बचना चाहती है। यह असंतुलन रिश्तों को खोखला कर रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं,बल्कि जिम्मेदारी उठाने की क्षमता होना चाहिए–यह बुनियादी समझ कहीं खो गई है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि हमारे माँ-बाप का समय अलग था। यह सच है कि तब दुनिया सरल थी,विकल्प कम थे। लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि तब भरोसा था। उन्होंने न काला देखा,न गोरा,न लंबी सूची बनाई,न परफेक्ट प्रोफ़ाइल ढूँढी। बुज़ुर्गों पर भरोसा किया,परिवार की सामूहिक बुद्धि पर विश्वास रखा और उसी भरोसे के सहारे जीवन जिया। यह नहीं कि तब समस्याएँ नहीं थीं,पर समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति नहीं थी।

आज समस्याएँ कम नहीं हुईं, बल्कि समाधान से भागने की आदत बढ़ी है। छोटी-छोटी असहमति को टॉक्सिक करार देकर रिश्ता तोड़ देना साहस नहीं,पलायन है। विवाह को आज़ादी का अंत समझा जाने लगा है, जबकि सच यह है कि सही साझेदारी ही व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता देती है। अकेले रहने का विकल्प सबके लिए संभव नहीं,और सबके लिए समाधान भी नहीं।

सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल ऐप्स ने अपेक्षाओं को बाज़ार बना दिया है। हर प्रोफ़ाइल तुलना का विषय है, हर विकल्प अस्थायी। बेहतर की खोज अंतहीन है,इसलिए पर्याप्त कभी मिलता ही नहीं। यह उपभोक्तावादी दृष्टि रिश्तों को भी उपभोग की वस्तु में बदल रही है–पसंद न आए तो बदल दो। लेकिन विवाह मोबाइल फ़ोन नहीं,जिसे हर साल अपग्रेड किया जाए,यह एक दीर्घकालिक सामाजिक अनुबंध है, जिसे निभाने की मानसिकता चाहिए।

आज शादी से ज़्यादा डर फँस जाने का है। यह डर बताता है कि हमने रिश्ते को सुरक्षा नहीं, बंधन के रूप में देखना शुरू कर दिया है। जबकि सच यह है कि रिश्ता बंधन नहीं, साझी जिम्मेदारी है–जहाँ दोनों को देना भी होता है और लेना भी। जहाँ बराबरी का अर्थ समानता नहीं,बल्कि न्याय और सम्मान होता है।

समाधान क्या है?

पहला—अपेक्षाओं की ईमानदार समीक्षा। क्या हम जो चाहते हैं, वह हम स्वयं देने में सक्षम हैं?

दूसरा—संवाद की बहाली। संवाद केवल बोलना नहीं, सुनना भी है। शादी से पहले ही नहीं,बाद में भी संवाद रिश्ते की रीढ़ है।

तीसरा—परिवार की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन। माता-पिता को दखल के खांचे से बाहर निकालकर मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना होगा।

चौथा—स्थानीय जीवन के सम्मान की वापसी। पेरिस का सपना बुरा नहीं,लेकिन अपने शहर,अपने काम और अपनी मिट्टी से शर्मिंदा होना आत्मघाती है।

यह पीढ़ी प्रतिभाशाली है,शिक्षित है, संभावनाओं से भरी है। इसमें दुनिया बदलने की क्षमता है। पर यदि रिश्तों में साहस नहीं होगा–समझौता करने का साहस,टिके रहने का साहस,साथ सीखने का साहस–तो भविष्य अनिश्चित रहेगा। शादी कोई परीक्षा नहीं,जिसमें शत-प्रतिशत अंक चाहिए हों,यह एक यात्रा है, जिसमें गिरते-पड़ते, सीखते हुए आगे बढ़ना होता है।

आज सवाल सिर्फ़ बुज़ुर्ग नहीं पूछ रहे– वक्त भी पूछ रहा है:-

क्या हम रिश्तों को शर्तों से आज़ाद कर पाएँगे?

क्या हम डर से बाहर निकलकर भरोसे की ओर लौटेंगे?

यदि उत्तर हाँ है, तो यह पीढ़ी भी बेहतर जिंदगी जी सकेगी।

और यदि उत्तर न है–तो कुंवारापन केवल वैवाहिक स्थिति नहीं, एक स्थायी सामाजिक अवस्था बन जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण से बजट तक:भविष्य के भारत की तलाश

ललित गर्ग
पटपड़गंज, दिल्ली-92

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाने वाला बजट केवल आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि वह देश की आर्थिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकताओं और भविष्य की संभावनाओं का दर्पण होता है। आज जब भारत एक ओर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और दूसरी ओर वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों,जलवायु संकट और तकनीकी परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब यह बजट और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत नागरिक से लेकर व्यापारी, उद्योगपति,किसान,श्रमिक,युवा और मध्यम वर्ग-सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं,क्योंकि इससे न केवल वर्तमान वर्ष की आर्थिक तस्वीर,बल्कि भविष्य के भारत की झलक भी मिलती है। बजट से पूर्व प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकार की सोच और नीति-दृष्टि के कई संकेत दिए हैं। इसमें विकास को केवल आंकड़ों की वृद्धि तक सीमित न रखकर अवसरों के विस्तार, समावेशी विकास और दीर्घ कालिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां अवश्य हैं, किंतु उनसे अधिक संभावनाएं हैं। यही दृष्टिकोण इस बजट का मूल स्वर होना चाहिए-चुनौतियों को अवसरों में बदलने का साहसिक प्रयास।

सबसे पहली और महत्वपूर्ण अपेक्षा निम्न वर्ग की क्रय-शक्ति बढ़ाने को लेकर है। किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती तभी आती है जब उसके सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सम्मानजनक जीवन जी सके और उपभोग में भागीदार बने। यदि निम्न आय वर्ग की आय बढ़ती है, उसे सस्ती और सुलभ सुविधाएं मिलती हैं,तो उसका सीधा प्रभाव मांग पर पड़ता है और मांग बढ़ने से उत्पादन,निवेश और रोजगार-तीनों को गति मिलती है। इसलिए इस बजट में प्रत्यक्ष नकद अंतरण, खाद्य सुरक्षा,स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च के साथ-साथ रोजगार सृजन के ठोस उपाय अपेक्षित हैं। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण,शहरी गरीबों के लिए भी समान प्रकृति की योजनाएं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। शहरी विकास इस बजट का एक और

प्रमुख केंद्र होना चाहिए। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और शहरों पर जनसंख्या, आवास,परिवहन,जल,स्वच्छता और पर्यावरण का दबाव लगातार बढ़ रहा है। केवल बड़े महानगरों पर निर्भरता अब व्यावहारिक नहीं रही। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा सुझाया गया शहरी विकेंद्रीकरण का विचार आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। छोटे और मध्यम शहरों को आर्थिक गति विधियों का केंद्र बनाना,उद्योगों और सेवाओं को वहां प्रोत्साहित करना,न केवल महानगरों पर बोझ कम करेगा बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन को भी घटाएगा। बजट में यदि टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए विशेष शहरी अवसंरचना पैकेज ,परिवहन नेटवर्क,डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल विकास योजनाएं लाई जाती हैं, तो यह दूरगामी परिवर्तन का आधार बन सकता है।

वैश्विक स्तर पर टैरिफ,व्यापार अवरोध और संरक्षणवाद की प्रवृत्तियां भारत के लिए चुनौती भी हैं और अवसर भी। अजय बंगा का यह कथन कि टैरिफ पर अधिक चिंता करने के बजाय व्यापारिक अवसरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए,भारत की वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त दृष्टि प्रदान करता है। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार,युवा जनसंख्या,डिजिटल क्षमताएं और उद्यमशीलता की प्रबल ऊर्जा है। यदि यह बजट निर्यात-उन्मुख उद्योगों,स्टार्ट-अप्स, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू-एडेड सेक्टर को प्रोत्साहन देता है, तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूत स्थान बना सकता है।'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को केवल नारों से आगे ले जाकर व्यावहारिक नीति समर्थन की आवश्यकता है-सरल कर संरचना, आसान ऋण, अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश और व्यापार करने में सुगमता के माध्यम से।

इस संदर्भ में मध्यम वर्ग की भूमिका को नजरअंदाज करना आर्थिक दृष्टि से आत्मघाती होगा। मध्यम वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है-वह सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा करदाता भी। विडंबना यह है कि बजट चर्चाओं में अक्सर यही वर्ग अपेक्षाकृत उपेक्षित रह जाता है। बढ़ती महंगाई,शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च,आवास ऋण और करों का बोझ मध्यम वर्ग की बचत और उपभोग दोनों को प्रभावित करता है। यदि इस बजट में आयकर स्लैब में तर्कसंगत सुधार,शिक्षा-स्वास्थ्य पर कर राहत और आवास को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाते हैं,तो इससे न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि मांग-आधारित विकास को भी बल मिलेगा। उद्योगों और व्यापार जगत के लिए बजट से अपेक्षा है कि वह स्थिर और पूर्वानुमेय नीति वातावरण प्रदान करे। निवेशक अनिश्चितता से डरते हैं। कर नीति में बार-बार बदलाव, अनुपालन की जटिलता और नियामक अस्पष्टता निवेश को बाधित करती है। इस बजट में यदि दीर्घकालिक कर-नीति का स्पष्ट संकेत,एमएसएमई सेक्टर के लिए सस्ता ऋण,तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन और हरित उद्योगों के लिए विशेष पैकेज दिए जाते हैं,तो यह उद्योगों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र,जो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, उसे आर्थिक पुनरुत्थान का केंद्र बनाया जाना चाहिए।

भविष्य के भारत की कल्पना केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं हो सकती। इसमें पर्यावरणीय स्थिरता,सामाजिक न्याय और मानवीय विकास समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हरित ऊर्जा,स्वच्छ परिवहन और टिकाऊ कृषि को बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा,बल्कि नए उद्योगों और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश भविष्य की कार्यशक्ति को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा,जबकि स्वास्थ्य पर खर्च एक स्वस्थ और उत्पादक समाज की नींव रखेगा। अंततः यह बजट एक संतुलन की परीक्षा है-राजकोषीय अनुशासन और विकासात्मक खर्च के बीच, अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों के बीच,तथा विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं के बीच। यदि यह बजट निम्न वर्ग की क्रय-शक्ति बढ़ाने,मध्यम वर्ग को राहत देने, शहरी विकेंद्रीकरण को गति देने और वैश्विक चुनौतियों को अवसरों में बदलने की स्पष्ट दिशा देता है,तो यह केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम का घोषणापत्र बन सकता है। देश को आज ऐसे ही बजट की आवश्यकता है,जो आशा जगाए,विश्वास पैदा करे और भविष्य के प्रति एक सकारात्मक,साहसिक दृष्टि प्रस्तुत करे।

शिक्षित युवा वर्ग के लिए बेरोजगारी समस्या नहीं मूल आवश्यकता है...

संजीव ठाकुर,
रायपुर छत्तीसगढ़

संभवतः अगली जनगणना के बाद भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा इसके अलावा सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला भी देश होगाद्य निश्चित तौर पर यह हमारे पर निर्भर है यह हमारी युवा जनसंख्या का उपयोग हम किस विकास की गति के साथ साथ तालमेल बिठाकर भारत राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। भारत का अधिकांश युवा रोजगार का तलबगार हो गया है,उसे सही मार्गदर्शन और नियोजन की योजना की जरूरत भी है। भारत की युवा और दीवा शक्ति के माध्यम से साइंस,टेक्नोलॉजी, मेडिकल,सेना,कंप्यूटर साइंस और स्वयं उद्यम के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत को अग्रणी देश बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब इस विशाल जनसंख्या का सीमित संसाधन पर कितना दबाव होगा,आप ये कल्पना कर सकते हैं। बहुत अधिक जनसंख्या देश में अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक समस्याओं को जन्म भी देती है। वर्तमान में भारत 142 करोड़ जनसंख्या (अनुमानित) के साथ विश्व में दूसरे नंबर पर है पहले नंबर पर चाइना 145 (अनुमानित) करोड़ की आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1989 से 11 जुलाई को हर वर्ष जनसंख्या दिवस के रूप में मनाता है पर जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या नियोजन पर भारत जैसे देश में कोई भी योजना नहीं बनती है। यही जनसंख्या बढ़ चुकी है और भारत में युवा जनसंख्या 60 प्रतिशत से ज्यादा है तो इसका सकारात्मक उपयोग ही किया जाना युक्ति युक्त होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत की जनसंख्या बाजार की ताकत है पर सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जनसंख्या विकास के लिए बड़ी बाधक भी है। अधिक जनसंख्या के दबाव में सीमित संसाधन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं आम जनता को उनकी मूल जरूरतों की आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पाती और यदि मिलती भी है तो बहुत ऊंची दरों में या बहुत महंगाई के बाद।ऐसे में देश में अनेक समस्याएं पैदा होती है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या के दबाव से विकास के लिए संकट खड़ा हो जाता है। विकास धीरे-धीरे मध्यम का अवरुद्ध हो जाता है। देश का आर्थिक नियोजन चरमराने लगता है। वर्ष 1951 से 81 के दशक को भारत की जनसंख्या की विस्फोटक अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर के तीव्र स्खलन और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ है। वर्ष 1921 तक की अवधि में भारत की जनसंख्या की वृद्धि स्थिर अवस्था में रही क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी निम्न थी। 1981 से लगातार अभी तक जनसंख्या की दर बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बढ़ती जनसंख्या के मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस स्लोगन परिवार नियोजन मानव का अधिकार रखा गया है, ताकि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के प्रति जागरूक होकर लोगों द्वारा परिवार नियोजन पर उत्साहजनक जोर दिया जाए। यह स्लोगन यह संकेत करता है कि सुरक्षित एवं शैक्षिक परिवार नियोजन एक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है और यह सभी लोगों को सशक्त बनाएगा और देश में विकास की गति को तेज करने में सहायक भी होगा। भारत की जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण बढ़ती जन्म दर और कम मृत्यु दर भी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश मैं बेरोजगारी गरीबी पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं चुनौती बनकर सामने आई जो समाज व्यक्ति और राष्ट्र सभी के विकास को अवरुद्ध करती है। हमारे पास उपलब्ध संसाधन इतनी बड़ी आबादी के लिए कतई पर्याप्त नहीं है। विकास और देश की समृद्धि के लिए जनसंख्या नियंत्रण एक आवश्यक अंग हो सकता है। कई यूरोपीय देशों ने अपनी बढ़ती जनसंख्या एवं संसाधनों में उचित तालमेल हेतु परिवार नियंत्रण प्रणाली को का निर्णय लिया किंतु एक समय बाद वहां कार्यशील जनसंख्या की अपेक्षा वृद्धों की संख्या में वृद्धि हुई जिससे मानव संसाधन की समस्याएं उनके सामने आने लगी हैं। चीन में पहले जनसंख्या नियंत्रण किया गया था। सरकार ने वैधानिक रूप से एक या दो बच्चे पैदा करने की शर्तें लागू की थी,पर वहां बुजुर्गों,वृद्धों की संख्या में भारी वृद्धि होने के पश्चात चीन की सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपनी जनता से अपील की है। जापान एक छोटा सा देश होने के बावजूद अपने सीमित संसाधनों के चलते अपने नवाचार तथा तकनीकी शक्ति के बल पर विकासशील देशों के समकक्ष खड़ा है। भारत जैसे विशाल देश में जहां बहुत बड़ी जनसंख्या भी है और विकास के लिए आवश्यक संसाधन भी हैं,विकास करने के लिए केवल विशाल जनसंख्या के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता होगी। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ उसके अनुपात में संसाधनों का संतुलन बना कर विकास की नई दिशा दी जा सकती है। संसाधनों की उचित दोहन हेतु सही और सटीक नीति तथा उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।

वीर सपूत

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं बिलासपुर

आज जो हम आजाद घूम रहे
जो भी है आज हमारी शान
आजादी के लिए जिन्होंने दे दी जान
ऐसे थे वो वीर सपूत महान
लूटी थी जिन्होंने सोने की चिड़िया
ले गए थे लूट कर सब समान
बेड़ियों में जकड़ी थी भारतमाता
जख्मी था दिल पांव थे लहूलुहान
आज भी सरहद पर खड़े हैं सीना तान
मेघ हों या बिजली कड़ाके होते नहीं परेशान
दुश्मन पर रहती है निगाह जैसे बाज की
कर देते है मिनटों में दुश्मन का काम तमाम
अमर हो जाते हैं वह जो हो जाते देश पर कुर्बान
इन्हीं वीर सपूतों से है आज मेरा भारत महान
दुनियां में बज रहा है डंका भारत के नाम का
झुकेगा नहीं बनी रहेगी इसकी शान

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

शहर महज आवास नहीं,आर्थिक अवसंरचना का हैं रूप

स्वराज श्रीवास्तव

आर्थिक सर्वेक्षण ने शहरों के अविकसित स्वरूप पर ध्यान दिलाया है, जो केवल आवास नहीं बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक अवसंरचना हैं। भारतीय शहर जीडीपी में योगदान बढ़ा रहे हैं, पर अनियोजित विकास, भीड़ और गंदगी से जूझ रहे हैं। नगर निकायों की नाकामी और राजस्व की कमी समस्याओं को बढ़ाती है। संतुलित व टिकाऊ विकास सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि राज्य सरकारें दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए योजनाएं लागू कर सकें। यह अच्छा है कि बजट से पहले संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में अनेक चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इनमें से एक है शहरों का सही तरह विकास न होना। चूंकि इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, इसलिए उसकी महत्ता भी समझी जानी चाहिए और उस पर गंभीरता से ध्यान भी दिया जाना चाहिए। इससे शायद ही कोई असहमत हो कि शहर महज आवास नहीं हैं। वे एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसंरचना का रूप हैं। इसीलिए उन्हें आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता है। हमारे शहर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे सुगम नागरिक जीवन के वैसे केंद्र नहीं बन पा रहे हैं, जैसे विश्व के अनेक देशों के शहर हैं। शहरी जीवन समस्याओं से घिर रहा है। वे तनाव, भीड़ और गंदगी का पर्याय

बन रहे हैं। ऐसा अनियोजित और बेतरतीब विकास के कारण हो रहा है। एक विडंबना यह भी है कि आधारभूत ढांचे में छिटपुट सुधारों को शहरी विकास का पर्याय मान लिया गया है। इसका परिणाम यह है कि शहरी समस्याएं रह-रहकर सिर उठाती रहती हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि कई शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन जाने के बाद भी राजनीतिक रूप से हाशिए पर ही रहते हैं। रही-सह कसर नगर निकायों की नाकामी पूरी कर देती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय शहर अपने राजस्व से सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत से भी कम प्राप्त करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि शहरों को सही तरह संचालित नहीं किया जा रहा है। प्रायः शहरों के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते समय इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि इससे शहरी जीवन का समुचित तरीके से विकास होगा या नहीं? शहरों में आर्थिक-व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र तो बना दिए जाते हैं, लेकिन इस पर कठिनाई से ही ध्यान दिया जाता है कि कामगार कहां रहेंगे या फिर उनका आवागमन कैसे होगा? जब शहर ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण,प्रदूषण आदि समस्याओं से घिरते हैं तो उनकी उत्पादकता प्रभावित होने के साथ ही उनमें निवेश की संभावना भी कम होती है। अब जब यह स्पष्ट है कि शहरों में आबादी का दबाव बढ़ते ही जाना है,तब फिर उनके संतुलित एवं टिकाऊ विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए शहरों में झुग्गी-बस्तियां बढ़ती जा रही हैं और आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक बनते जा रहे हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि आर्थिक सर्वेक्षण में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए जो योजनाएं शुरू करने की जरूरत जताई गई है, उनकी पूर्ति करने के लिए राज्य सरकारें आगे आएं। वे यह समझें कि अपने शहरों का सही तरह विकास करना उनका ही काम है और यह इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ही समृद्धि आएगी।

हर बजट में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य : मंत्री ओपी चौधरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश किया। यह उनका नौवां बजट है। बजट के बाद छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं सरगुजा प्रभारी मंत्री ने अंबिकापुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर केन्द्र सरकार के बजट की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करने वाला है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच देश पॉलिसी पैरालिसिस और आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें स्थान पर थी और गठबंधन सरकारों की मजबूरियों से देश प्रभावित था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था ने तेजी से प्रगति की है और अब भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। आने वाले समय में भारत के तीसरे स्थान पर पहुंचने की पूरी संभावना है। हर बजट में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केंद्र में रखा जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी

अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। रेलवे को अर्थव्यवस्था की बुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 22 गुना वृद्धि की गई है। बजट में रेयर अर्थ मिनरल्स के विकास पर भी विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही 7 हाई स्पीड रेल परियोजनाओं और वाटर इकॉनमी को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, अनिल सिंह मेजर, महापौर मंजूषा भगत सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

घाटे में छोड़ गई थी कांग्रेस

वित्त मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को चरमराकर छोड़ दिया था। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इस योजना में 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी छोड़ी गई थी। उन्होंने बताया कि पुरानी बकाया देनदारियों को निपटाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा छोड़े गए आर्थिक गड्ढों को भरते हुए राज्य सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है।

आईटीआर संशोधन की प्रक्रिया का सरलीकरण व्यापारियों के लिए बड़ी राहत...विशेषज्ञों की राय

केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रस्तुतीकरण के पश्चात सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में उत्साह का माहौल देखा गया। वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी की उपस्थिति में बजट श्रवण कर रहे नगर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यापारियों और प्रबुद्धजनों ने बजट को 'समावेशी' और 'विकसित भारत' की आधारशिला बताया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस

भारत विकास परिषद की प्रांतीय कार्यसमिति के सदस्य सीए शरद अग्रवाल ने बजट का विश्लेषण करते हुए कहा कि यह बजट पूरी तरह से बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर जोर देने से न केवल विकास कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के स्वतः अवसर सृजित होंगे। पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से बाहर आना सरकार की 'अंत्योदय' नीति की बड़ी सफलता है।

व्यापारी वर्ग में हर्ष: MSME और ITR नियमों में राहत

व्यापारिक जगत ने बजट के प्रावधानों का पुरजोर स्वागत किया है। कैट के प्रदेश मंत्री अमित अग्रवाल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं,कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र तिवारी और अग्रवाल महासभा के उपाध्यक्ष समीर अग्रवाल ने 'आयकर रिटर्न' में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मामूली टैक्स के साथ आईजीआर रिवाइज करने की सुविधा से व्यापारियों को तकनीकी त्रुटियों के कारण होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।

स्वास्थ्य और पर्यावरण: आम आदमी को मिली बड़ी सौगात

बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर की गई घोषणाओं ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। सभी ने एक सुर में कैंसर सहित 10 गंभीर बीमारियों की जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स कम करने के निर्णय को 'संवेदनशील कदम' बताया। कैट के पूर्व जिला उपाध्यक्ष उपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि यह बजट गरीब, मरीज और व्यापारी तीनों के हितों का संरक्षण करता है। साथ ही, ग्रीन एनर्जी और सोलर सिस्टम के दामों में कमी से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

सरगुजा के विकास को मिलेगी गति

व्यापारी संगठन का मानना है कि इस बजट से न केवल देश बल्कि छत्तीसगढ़ और विशेषकर सरगुजा अंचल के व्यापारिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति इस 'संतुलित और दूरदर्शी' बजट के लिए आभार व्यक्त किया है।

आम बजट 2026-27 पर सियासी घमासान...भाजपा ने बताया विकासोन्मुखी,कांग्रेस ने कहा जनविरोधी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा भी की गई है। बजट को लेकर जिले में राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

भाजपा ने सराहा,बताया दूरदर्शी बजट : भाजपा नेताओं ने बजट को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया है। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग की क्षमता बढ़ाने और समावेशी विकास को गति देने वाला है। उन्होंने आयकर स्लैब में बदलाव,12 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट, वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने को स्वागतयोग्य बताया। भाजपा नेता मधुसूदन शुक्ला ने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास और सरकारी खरीदी में एमएसएमई को प्राथमिकता देना सकारात्मक कदम है। व्यापारी संगठनों ने भी बजट का समर्थन किया। कैट जिला अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि सात रेलवे कॉरिडोर से माल परिवहन सुगम होगा और वस्तुएं सस्ती होंगी। कैंसर व डायबिटीज की दवाइयों के दाम

घटने से आमजन को राहत मिलेगी। सीए पुष्पराज सिंघल और शरद अग्रवाल ने बजट को करदाताओं के प्रति भरोसे का प्रतीक बताते हुए कहा कि आयकर विवादों को कम करने के लिए सरकार ने कई व्यावहारिक रियायतें दी हैं।

कांग्रेस ने साधा निशाना : वहीं कांग्रेस नेताओं ने बजट को निराशाजनक और जनविरोधी करार दिया है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकल झा ने कहा कि युवाओं के रोजगार को लेकर बजट पूरी तरह विफल है। 1 करोड़ युवाओं के लिए घोषित इंटर्नशिप योजना अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने बजट को देश के 0.5 प्रतिशत अमीरों का बजट बताते हुए कहा कि इसमें किसान,मजदूर,महिला,युवा और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नेत्री नीति सिंहदेव ने कहा कि यह बजट गरीबों और बेरोजगारों को और कमजोर करेगा तथा केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है।

साढ़े 7 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ झारखंड के तीन सप्लायर गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है। टीम ने नशीले इंजेक्शन के अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नशीले इंजेक्शन का मुख्य सप्लायर रंजीत विश्वकर्मा भी शामिल है। तीनों आरोपियों को 1500 नग नशीले इंजेक्शन के साथ रामानुजगंज से पकड़ा गया है। जब्त इंजेक्शन की कीमत करीब साढ़े 7 लाख रुपए आंकी गई है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि संभागीय उडऩदस्ता टीम ने 30 जनवरी को गोदरमाना (झारखंड) निवासी अनूप गुप्ता और बतौली (सरगुजा) निवासी विनय गुप्ता को 1200 नग नशीले इंजेक्शन के साथ बतौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अनूप गुप्ता ने बताया कि वह ये नशीले इंजेक्शन झारखंड के गढ़वा जिले के रंजीत विश्वकर्मा से खरीदता था। उसने यह भी बताया कि रंजीत विश्वकर्मा के साथ मंजूर अंसारी और प्रमोद भी इस अवैध

कारोबार में शामिल हैं। तीनों मिलकर नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करते थे। मुख्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने डीआईजी सरगुजा राजेश अग्रवाल से साइबर सेल की मदद मांगी। साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपियों के मोबाइल लोकेशन ट्रेस किए गए। इसके बाद 31 जनवरी की शाम आबकारी उडऩदस्ता टीम ने पलटन घाट, रामानुजगंज से रंजीत विश्वकर्मा, मंजूर अंसारी और प्रमोद को गिरफ्तार किया। टीम ने बताया कि तीनों आरोपी बाइक से नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करने आए थे। उनके कब्जे से 1500 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

साइबर सेल की भूमिका रही अहम

सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि साइबर सेल की मदद के बिना यह कार्रवाई संभव नहीं थी। डीआईजी राजेश अग्रवाल के सहयोग से साइबर सेल की टीम को जोड़ा गया,जिससे अंतर्राज्यीय मुख्य तस्करों तक पहुंच बनाई जा सकी। इस कार्रवाई में साइबर सेल के अजीत मिश्रा, भोजराज पासवान,जितेश साहू,विकास सिन्हा,लीना तिर्की तथा आबकारी उडऩदस्ता टीम के अशोक सोनी,गणेश पांडेय,रणविजय सिंह,ओमप्रकाश गुप्ता,चंद्रावती और नीरज चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

50 प्रतिशत अवैध कारोबार पर लग सकती है रोक

सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि रंजीत विश्वकर्मा और उसके दोनों साथियों की गिरफ्तारी से सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार पर करीब 50 प्रतिशत तक रोक लगने की संभावना है। रंजीत विश्वकर्मा बड़ा सप्लायर था,जबकि मंजूर अंसारी और प्रमोद इंजेक्शन की डिलीवरी का काम करते थे।

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में नगर बंद का रहा आंशिक असर,कानून वापस लेने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में 1 फरवरी को आहूत अंबिकापुर बंद का असर आंशिक रूप से देखने को मिला। स्वर्ण समाज ने सर्वसम्मति से बंद को सफल बनाने की अपील की थी। इसके समर्थन में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सुबह रैली के रूप में निकलकर शहर में बंद का आह्वान किया। सुबह के समय बाजार में बंद का असर स्पष्ट नजर आया।

कई प्रमुख इलाकों में दुकानें बंद रहीं और आवागमन भी सामान्य से कम रहा। हालांकि, दोपहर होते-होते स्थिति सामान्य होने लगी और अधिकांश दुकानें खुल गईं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने यूजीसी नियम को समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी और जनविरोधी बताते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यूजीसी संशोधन

कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत की परंपरा हजारों वर्षों से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की रही है। लेकिन यूजीसी का नया संशोधन प्रस्ताव इस मूल भावना के विपरीत प्रतीत होता है। जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का हित होना चाहिए, न कि किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा या अपमान। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित संशोधन नियमों से कथित रूप से कुछ वर्गों, विशेषकर ब्राह्मण,क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ समाज के प्रति दुराग्रह और उपेक्षा का भाव झलकता है। कहा गया है कि यह वही समाज है, जिसने सदियों से राष्ट्र,धर्म और संस्कृति की रक्षा में निरंतर योगदान दिया है।

समाज में विभाजन की आशंका : संगठनों का कहना है कि इस तरह के कानून से समाज में जातिगत विद्वेष बढ़ सकता है और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंच सकता है। इससे न केवल समाज, बल्कि पूरे राष्ट्र की भावनाएं आहत होंगी और देश प्रगति के बजाय पीछे की ओर जा सकता है।

काला कानून बताकर वापस लेने की मांग : ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह किया गया है कि इस अदूरदर्शी, समाज विरोधी और जनविरोधी कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ज्ञापन पर स्वयं को समाज और राष्ट्रप्रेमी बताने वाले लोगों के हस्ताक्षर दर्ज हैं।

सड़क हादसे में महिला की मौत

-संवाददाता-
लखनपुर,01 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

लखनपुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-130 पर एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा घायल हो गया। हादसा 31 जनवरी 2026 की शाम लगभग 6 बजे सिंगीटाना पेट्रोल पंप के पास हुआ। मृतका की पहचान 55 वर्षीय दशमेत राजवाड़े पत्नी देवप्रसाद राजवाड़े,निवासी ग्राम पीपरखार थाना लखनपुर जिला सरगुजा के रूप में हुई है। घायल बेटे का नाम शिवप्रकाश राजवाड़े (उम्र लगभग 35 वर्ष) बताया गया है। पुलिस सूत्रों और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दशमेत और उनका बेटा शिवप्रकाश मोटरसाइकिल पर ग्राम पीपरखार से सिंघोटाना आए थे, जहां उन्होंने मोटर बेचने के बाद शाम करीब 6 बजे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे।

इसी दौरान अंबिकापुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने लापरवाही से चलते हुए उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर पड़े। हादसे में दशमेत को सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जबकि शिवप्रकाश के बाएं पैर की उंगली में चोट लगी। सूचना मिलते ही 112 एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मणपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दशमेत को मृत घोषित कर दिया। शिवप्रकाश का इलाज जारी है। हादसे की सूचना दशमेत के पति देवप्रसाद राजवाड़े के पुत्र कमलेश राजवाड़े उम्र 35 वर्ष ने दी, पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज की है। जांच में लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक की भूमिका सामने आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषी चालक की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सड़क किनारे बोरे में मिला एक दिन का नवजात लड़का,इलाके में मचा हड़कंप

-संवाददाता-
सूरजपुर,01 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के ओडगी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपुर गांव के पास जंगल के रास्ते में सड़क किनारे एक दिन का नवजात शिशु बोरे में बंद मिला। बच्चे को कंबल में लपेटकर फेंका गया था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार,सड़क से गुजर रहे ग्रामीणों को बोरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब ग्रामीण रुके और बोरा खोला तो अंदर नवजात शिशु को देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद तत्काल बच्चे को भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

नवजात लड़का है... स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि नवजात लड़का है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। एहतियात के तौर पर बच्चे को बेहतर इलाज के लिए सूरजपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नवजात को इस हाल में कौन और क्यों छोड़ गया।

पहले बर्थ-डे का केक काटा फिर पत्नी का गला घोंटकर चाकू से रेत दिया गला...गैरमर्द से संबंध का था शक

सूरजपुर जिले के जयनगर थाना अंतर्गत मोरभंज डेम के जंगल में मिली युवती की हत्या की गुत्थी सुलझी,पति ही निकला हत्यारा

-संवाददाता-
सूरजपुर,01 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरभंज डेम से लगे जंगल में 30 जनवरी को एक युवती का गला रेता शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को उसे जेल भेज दिया। आरोपी को पत्नी के गैरमर्द से अवैध संबंध का शक था। वह उसकी हत्या करने की कई दिनों से योजना बना रहा था। इसी बीच 29 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन उसे मोरभंज डेम घूमाने की बात कहकर ले गया था। यहां उसने पहले केक काटा फिर पत्नी के स्टॉल से उसका गला घोंट दिया। फिर चाकू से गला रेतकर हत्या करने के बाद शव जंगल में फेंक दिया था। अंबिकापुर के गांधीनगर निवासी रिंकी पाटिल ने जयनगर

थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी बड़ी बहन पिंकी सोलंकी 29 जनवरी को दोपहर करीब 12.30 बजे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। संपर्क करने पर उसका मोबाइल स्वीच ऑफ आ रहा था। इसी बीच 30 जनवरी ग्राम मोरभंज डेम के पास जंगल किनारे एक युवती का शव मिलने की सूचना पर वह पहुंची। उसने शव की पहचान अपनी बहन पिंकी के रूप में की। शव की हालत बेहद भयावह थी। गले में धारदार हथियार से काटने के गहरे निशान थे। उसने बहन के दूसरे पति हेमंत उर्फ गोलू पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने एसएसपी प्रशांत ठाकुर के निर्देश एवं एसडीओपी अभिषेक पैकरा के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की की।

चरित्र शंका पर हत्या की स्वीकारी बात : शक के आधार पर पुलिस ने मृतिका के पति हेमंत उर्फ गोलू को बिश्रामपुर बस स्टैंड में घेराबंदी कर पकड़ा। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि मृतिका उसकी पत्नी थी और वह उस पर चरित्र शंका करता था। इसी शक के चलते वह लंबे समय से उसे जान से मारने की फिराक में था। 29 जनवरी को आरोपी का जन्मदिन था,इसी बहाने वह पत्नी को घुमाने ले जाने का झांसा देकर बाइक क्रमांक सीजी 16 सीएस 3152 से अंबिकापुर के एक होटल ले गया। यहां दोनों ने खाना खाया। इसके बाद वह उसे मोरभंज डेम के पास जंगल में ले गया। जंगल में आरोपी ने पहले जन्मदिन का केक काटा, शराब पी और फिर पूरी योजना के तहत पत्नी के गले में स्टॉल से फंदा बनाकर कस दिया। इसके बाद धारदार चाकू से गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर फरार हो गया।

डेम में फेंक दिया था चाकू : आरोपी ने बताया कि उसने हत्या में प्रयुक्त चाकू डेम में फेंक दिया था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और बाइक जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी हेमंत सोलंकी पिता कृष्ण कुमार सोलंकी 24 वर्ष निवासी पंडोपारा थाना पटना जिला कोरिया, स्थायी पता ग्राम पंचायत कुसमुसी भैयाथान को 1 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। कार्रवाई में जयनगर थाना प्रभारी निरीक्षक रूपेश कुंतल एक्का, सहायक उप निरीक्षक शशि शेखर तिवारी, मनोज द्विवेदी, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र कुमार एक्का, रविशंकर पांडेय, आरक्षक अंबिका प्रसाद मरावी, सुरेश साहू, हरिशंकर सिंह, जितेन्द्र सिंह सहित अन्य शामिल रहे।

स्वास्थ्य कर्मचारियों के हितों को मिलेगी नई धार....

विमल बने छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष

दिलीप पाण्डेय सोनहत,अमरनाथ साहू बैकुण्ठपुर और रोशन कुमार बचरापोंडी के अध्यक्ष मनोनीत

बृज कुमार साहू को सर्वसम्मति से कार्यकारी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी,बैकुण्ठपुर में भव्य शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

-संवाददाता-
कोरिया,01 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विमल मिंज को कोरिया जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, यह नियुक्ति संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल पाण्डेय द्वारा 19 दिसंबर 2025 को आयोजित प्रांतीय बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर की गई,बैठक में प्रांतीय सचिव आर.पी. गौतम, प्रांतीय संगठन सचिव एस.एस. जयसवाल,निवर्तमान जिलाध्यक्ष एस.एस. राजवाड़े सहित प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में हुआ यह संगठनात्मक परिवर्तन केवल पदों का बदलाव नहीं, बल्कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के अधिकारों को नई दिशा देने की शुरुआत माना जा रहा है,अब निगाहें नए नेतृत्व पर टिकी हैं जिससे कर्मचारियों को उम्मीद है कि संघर्ष,संवाद और संगठन की ताकत से उनके अधिकारों को मजबूती मिलेगी।

सर्वसम्मति से हुआ नेतृत्व परिवर्तन-

बैठक में प्रदेशभर के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की वर्तमान चुनौतियों–वेतन विसंगति,सुरक्षा,भत्ते,पदोन्नति एवं कार्यस्थल समस्याओं–पर विस्तार से चर्चा की, सभी सदस्यों की राय थी कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए ऊर्जावान, संघर्षशील और कर्मठ नेतृत्व की आवश्यकता है, इसी भावना के साथ विमल मिंज को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।

प्रांताध्यक्ष अनिल पाण्डेय ने जताया भरोसा

नियुक्ति पत्र जारी करते हुए प्रांताध्यक्ष अनिल पाण्डेय ने कहा विमल मिंज लंबे समय से स्वास्थ्य कर्मचारियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं,उनकी कार्यशैली,समर्पण और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है,हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जिला इकाई और अधिक मजबूत होगी तथा कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विमल मिंज का संकल्प

पदभार ग्रहण करने के पश्चात विमल मिंज ने कहा मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर संगठन ने जो विश्वास जताया है,वह मेरे लिए सम्मान ही नहीं बल्कि हजारों स्वास्थ्य योद्धाओं की सेवा का संकल्प है, यह पद मेरे लिए अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है।

आगामी कार्ययोजना व विजन

उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी हित सर्वोपरि रहेंगे,वेतन विसंगति,भत्तों व सुविधाओं की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, प्रशासन और कर्मचारियों के बीच संवाद से समाधान की नीति अपनाई जाएगी,अंतिम पंक्ति के कर्मचारी तक संगठन पहुंचेगा,उन्होंने कहा हम टकराव नहीं,ठोस संवाद में विश्वास रखते हैं,लेकिन कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा।

सुरक्षा और सम्मान पर सख्त रुख

विमल मिंज ने दो टूक शब्दों में कहा अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी रेड-लाइन है,ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम भयमुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करेंगे,उन्होंने जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मियों से मतभेद भुलाकर संगठन के झंडे तले एकजुट होने की अपील की।

ब्लॉक स्तर पर भी नई जिम्मेदारियां संगठन विस्तार के तहत

- **दिलीप पाण्डेय**–विकासखंड सोनहत अध्यक्ष
- **अमरनाथ साहू**- विकासखंड बैकुण्ठपुर अध्यक्ष
- **रोशन कुमार**–बचरापोंडी विकासखंड अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

दिलीप पाण्डेय ने कहा कि सोनहत के दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा एवं लंबित भत्तों का भुगतान उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

बृज कुमार साहू बने कार्यकारी जिलाध्यक्ष

संगठन ने सर्वसम्मति से बृज कुमार साहू को कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया, इस निर्णय का कर्मचारियों ने तालियों के साथ स्वागत किया।

सांस्कृतिक भवन बैकुण्ठपुर में भव्य समारोह

31 जनवरी को सांस्कृतिक भवन,बैकुण्ठपुर में आयोजित कार्यक्रम में निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर जायसवाल का विदाई समारोह,नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विमल मिंज का स्वागत, सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एक ही मंच पर सम्पन्न हुआ,कार्यक्रम में विकासखंड सोनहत, बैकुण्ठपुर, बचरापोंडी एवं जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर के बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारी रहे मौजूद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से

- आर.डी. दीवान - कार्यकारी प्रांताध्यक्ष
- आर.पी. गौतम - वरिष्ठ प्रांतीय सचिव
- सिंगार साय राजवाड़े - प्रांतीय संगठन सचिव
- राजकुमार जायसवाल
- सत्येंद्र सिंह (निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष)
- रामकुमार सिंह (बचरापोंडी) सहित बड़ी संख्या में संघ पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

कर्मचारियों में उत्साह की लहर : विमल मिंज की नियुक्ति के बाद नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल कर्मचारी, मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी वर्गों में भारी उत्साह देखा गया, कर्मचारियों का मानना है कि उनके नेतृत्व में कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, लंबित मांगों को नई गति मिलेगी संगठन जमीनी स्तर पर और मजबूत होगा

कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम से हजारों विद्यार्थियों को मिली नई दिशा

आत्मविश्वास,कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से ही साकार होंगे सपने : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

-संवाददाता-
सूरजपुर,01 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर, लक्ष्यनिष्ठ और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में एक और प्रेरणादायक पहल सामने आई है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर जिले के भटगांव स्थित स्टेडियम ग्राउंड में कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया,इस कार्यक्रम में 6 से 8 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपने भविष्य और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया,आयोजन स्थल विद्यार्थियों के जोश,आत्मविश्वास और सीखने की ललक से पूरी तरह ऊर्जा से भरा नजर आया,कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सरकार, समाज और विशेषज्ञ एक मंच पर आते हैं,तो युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलती है,यह आयोजन सूरजपुर जिले के युवाओं के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा।

युवा ही राष्ट्र के भविष्य के निर्माता : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा आज का युवा ही देश और समाज के भविष्य का निर्माता है,राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है,जिसे स्पष्ट लक्ष्य,सही मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम से ही पूरा किया जा सकता है,उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियां व्यक्ति को कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाती हैं। सही समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने शिक्षा को सफलता की सबसे मजबूत नींव बताते हुए विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपनी रुचि और क्षमता को पहचानें, मूल्यों और जीवनशैली को ध्यान में रखकर करियर चुनें, ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ लें।

'सोच ऊंची होगी तो उड़ान भी ऊंची होगी' - एन वी सर

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देश के प्रख्यात करियर मार्गदर्शक, कोटा (राजस्थान) स्थित मोशन कोचिंग सेंटर के संस्थापक एवं सीईओ नितिन विजय (एन वी सर) रहे, उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी,लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास निर्माण और करियर चयन पर अत्यंत प्रभावशाली मार्गदर्शन दिया, एन वी सर ने कहा 'सोच ऊंची रखो, उड़ान भी ऊंची होगी,सफलता दो बार मिलती है, पहले मन में और फिर वास्तविक जीवन में,उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि सफलता केवल पढ़ाई से नहीं,बल्कि सही रणनीति, निरंतर अभ्यास,आत्मचिंतन और गलतियों से सीखने की क्षमता से प्राप्त होती है,उन्होंने युवाओं से करियर चयन से पूर्व अपनी रुचि, क्षमता और व्यक्तित्व को समझने की अपील की तथा सोशल प्रेशर में आकर निर्णय न लेने की सलाह दी।

जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से रामसेवक पैकरा - अध्यक्ष,छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रमणी देवपाल सिंह पैकरा,राम कृपाल साहू,परमेश्वरी राजवाड़े,रजनी त्रिपाठी,भीमसेन अग्रवाल, राजेश महलवाला,ठाकुर राजवाड़े,नूतन विश्वास,अनुज राजवाड़े,अशोक राजवाड़े, रेखा राजवाड़े,रमेश गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि मंचासीन रहे,प्रशासनिक स्तर पर जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र पाटले, एसडीएम चाँदनी कंवर,जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल,अन्य अधिकारीगण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बाल विवाह उन्मूलन और नशा मुक्त भारत का लिया संकल्प

कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी विद्यार्थियों, युवाओं एवं नागरिकों ने बाल विवाह उन्मूलन,नशा मुक्त भारत के लिए सामूहिक शपथ लेकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश दिया।

हजारों विद्यार्थियों के लिए बना प्रेरणा का मंच

कपिध्वज करियर गाइडेंस कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए केवल एक सेमिनार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास जगाने वाला मंच, लक्ष्य तय करने की दिशा, और भविष्य निर्माण का मजबूत आधार साबित हुआ, कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों में नए उत्साह, स्पष्टता और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

न्यायालय तहसीलदार प्रेमनगर ,जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क0/...../अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण निवासी ग्राम रघुनाथपुर रा.नि.मं. प्रेमनगर तहसील प्रेमनगर को सूचित किया जाता है कि आवेदिका जानकी पिता स्व. बोधनराम जाति चमार निवासी ग्राम रघुनाथपुर तहसील प्रेमनगर द्वारा ग्राम रघुनाथपुर तहसील प्रेमनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर 379, 389,380 रकबा क्रमशः 0.12, 0.35, 0.63 हे कुल खसरा नम्बर 03 कुल रकबा 1.10 हे. भूमि आवेदिका एवं अनावेदकगण शांति राम, रामभरोष आ. स्व. बोधन राम के नाम पर संयुक्त खाते में दर्ज है। उभयपक्ष द्वारा आपसी बटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त करते आ रहे है। खाता पृथक नही होने के कारण खाता विभाजन 1/3 हिस्सा में बटवारा कराने आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त आवेदित भूमि पर बटवारा किये जाने पर जिस किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई दिनांक 05.02.2026 के पूर्व दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
प्रेमनगर,सूरजपुर,छ0ग0

जिला कांग्रेस ने नहीं किया आयोजन शहर व ब्लॉक कांग्रेस ने संभाली कमान

महात्मा गांधी के बलिदान दिवस पर 'मनरेगा बचाओ संग्राम' का आगाज

-संवाददाता-
सूरजपुर,01 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

पार्टी के प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला,शहर एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे,किंतु जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कोई आयोजन नहीं किया गया,इसके विपरीत शहर कांग्रेस एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पार्टी निर्देशों का पालन करते हुए 'मनरेगा बचाओ संग्राम' कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार की नीतियों के विरुद्ध विरोध दर्ज कराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज डालमिया एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जफर हैदर के संयुक्त नेतृत्व में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई,इसके पश्चात माता कर्मा चौक के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक चक्का जाम किया गया,जहां जिला कांग्रेस की निष्क्रियता चर्चा का विषय बनी रही, वहीं शहर व ब्लॉक कांग्रेस ने संगठनात्मक जिम्मेदारी निभाते हुए सड़कों पर उतरकर किसानों और मजदूरों की आवाज बुलंद की,मनरेगा बचाओ संग्राम' के माध्यम से कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिया कि किसान और मजदूर हितों से जुड़ा हर मुद्दा सड़क से सदन तक उठाया जाएगा।

धान खरीदी तिथि बढ़ाने की उठी मांग

धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर सूरजपुर को ज्ञापन सौंपा,नेताओं ने कहा कि किसानों का धान अब तक पूरा नहीं खरीदा गया है, समय सीमा कम होने से किसान परेशान हैं, कई किसानों के टोकन नहीं कट पाए हैं, खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं,ऐसी स्थिति में धान खरीदी की तिथि बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है,ताकि किसानों को राहत मिल सके।

मनरेगा से छेड़छाड़ का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा योजना का नाम व स्वरूप बदलने का प्रयास कर रही है, जो गरीब मजदूरों के साथ सीधा अन्याय है, उन्होंने कहा मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ है, बलिदान दिवस के अवसर पर कांग्रेसजनों ने मांग की कि मनरेगा योजना को पूर्ववत यथावत रखा जाए और मजदूरों के अधिकारों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए।

कांग्रेस नेताओं ने जताया आक्रोश

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार किसान व मजदूर विरोधी नीतियां अपना रही है, योजनाओं को कमजोर कर गरीबों से उनका हक छीना जा रहा है, यदि समय रहते सरकार ने निर्णय नहीं बदला,तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रहे उपस्थित

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन व कार्यकर्ता मौजूद रहे,जिनमें प्रमुख रूप से भगवती राजवाड़े - पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष,नरेश राजवाड़े-पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष,अश्विनी सिंह - पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, रामकृष्ण ओझा - जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, राजीव सिंह - जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष, मनोज अग्रवाल, हेमेन्द्र गुप्ता, गैबीनाथ साहू, विष्णु कसेरा, वीरेन्द्र बंसल, आशीष यादव, अविनाश यादव, आकाश साहू - एनएसयूआई जिलाध्यक्ष जाकेश राजवाड़े, नीरज तायल, धर्मेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र मिश्रा, भावना सिंह नेताम, सूरज अवस्थी, हुपेश प्रजापति, मधु साहू, राम सिंह, मुस्तफा खान, विनय सिंह, सैयद नदीम, अफरोज अंसारी, लिवनेश सिंह, शाहरुख खान, मनोज सिंह, बाबूलाल सिंह, दीपक दीवान, तनवीर, सुमंत राजवाड़े, यशवंत सिंह, निलेश, कमलेश सिंह, संजय अग्रवाल, हरक लाल राजवाड़े, मनोज सोनी, हैदर अली सहित शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

CMYK

दैनिक घटती घटना ने जारी किया

2026 का वार्षिक कैलेंडर

उत्कृष्ट गुणवत्ता और आकर्षक डिज़ाइन को मिली सराहना

उपयोगी जानकारियों से सुसज्जित दैनिक घटती-घटना 2026 कैलेंडर का विमोचन

भव्य आयोजन के साथ दैनिक घटती-घटना वर्ष 2026 कैलेंडर का हुआ विमोचन

जानकारी,गुणवत्ता और विश्वास का संगम दैनिक घटती-घटना 2026 कैलेंडर का लोकार्पण

दैनिक घटती-घटना 2026 कैलेंडर विमोचन समारोह बना पत्रकारिता और जनसेवा का प्रतीक

-न्यूज डेक-

कोरिया,01 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

लोकप्रिय एवं जनपक्षधर समाचार पत्र दैनिक घटती-घटना द्वारा तैयार किए गए वर्ष 2026 के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन गरिमामय समारोह के बीच संपन्न हुआ,इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों,पत्रकारों एवं गणमान्य नागरिकों ने कैलेंडर की गुणवत्ता, विषय-वस्तु और आकर्षक प्रस्तुति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की,दैनिक घटती-घटना द्वारा विशेष रूप से तैयार यह कैलेंडर वर्ष भर आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके,इस उद्देश्य से तैयार किया गया है। कैलेंडर में तिथियों, पर्व-त्योहार,राष्ट्रीय अवकाश, महत्वपूर्ण दिवसों सहित दैनिक जीवन से जुड़ी अनेक आवश्यक जानकारियों को अत्यंत सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वर्ष 2026 का यह वार्षिक कैलेंडर उत्कृष्ट गुणवत्ता,आकर्षक प्रस्तुति और व्यापक जानकारी के कारण लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना,दैनिक घटती घटना का यह प्रयास निश्चित रूप से पाठकों के विश्वास और संस्थान की विश्वसनीयता को और मजबूत करेगा।

बता दे की छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक घटती-घटना के वर्ष 2026 के वार्षिक कैलेंडर का भव्य विमोचन शनिवार को स्थानीय रेस्ट हाउस, बैकुंठपुर में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ,यह आयोजन केवल कैलेंडर विमोचन तक सीमित नहीं रहा,बल्कि जनहित,निष्पक्ष पत्रकारिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा संकल्प का सशक्त मंच बना,कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े,पूर्व विधायक गुलाब कमरो, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी,जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा,उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश शुक्ला,वेदांती तिवारी,शैलेन्द्र सिंह,शैलेश शिवहरे,आशीष यादव,गायत्री सिंह,अनुराग दुबे,कमलेश शर्मा,पूर्व महापौर के. डमरू रेड्डी सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि,पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संवाददाताओं की प्रतिक्रिया

पत्रकारिता का उद्देश्य समाज की विसंगतियों को उजागर करना और जनता को जागरूक करना है। जब आप सच के साथ खड़े होते हैं,तो पूरा समाज आपके साथ खड़ा होता है।

ओंकार पाण्डेय (संवाददाता,घटती-घटना)

घटती-घटना का मुख्य उद्देश्य समाज के साथ-साथ शासन-प्रशासन की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना है, ताकि उन विसंगतियों को दूर किया जा सके और समाज के हर तबके को उसका हक व अधिकार मिल सके। आज का यह सफल आयोजन स्पष्ट करता है कि घटती घटना हमेशा समाज के साथ खड़ा है।

राजेन्द्र शर्मा (संवाददाता,घटती-घटना)

हमारा उद्देश्य केवल खबर पहुंचाना नहीं,बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के दर्द को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है। आज जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति हमारे संकल्प को और मजबूत करती है।

राजन पाण्डेय (संवाददाता,घटती-घटना)

पत्रकारिता हमारे लिए केवल पेशा नहीं,बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। दबाई गई आवाजों को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। यह आयोजन हमें और अधिक निष्पक्षता से कार्य करने की ऊर्जा देता है।

रवि सिंह (संवाददाता,घटती-घटना)

पत्रकारिता का मूल धर्म सत्ता की प्रशंसा नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को बेबाकी से उजागर करना है। हमारी टीम पूरी ईमानदारी से इस संकल्प पर कार्य कर रही है।

शमरोज खान (संवाददाता,घटती-घटना)

अतिथियों को आया बेहद पसंद

कैलेंडर विमोचन के दौरान उपस्थित अतिथियों ने इसकी क्वालिटी, क्लेवर डिज़ाइन और उपयोगिता की जमकर सराहना की, कई अतिथियों ने कहा कि यह कैलेंडर न केवल देखने में सुंदर है,बल्कि दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी भी है,अतिथियों का कहना था कि कैलेंडर ऐसा होना चाहिए जो पूरे वर्ष लोगों को सही जानकारी दे सके, और दैनिक घटती-घटना का 2026 कैलेंडर इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है।

डिजाइन और गुणवत्ता रही विशेष आकर्षण

2026 के इस कैलेंडर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बेहतर प्रिंटिंग क्वालिटी,संतुलित रंग संयोजन और आकर्षक कवर डिज़ाइन रही,कैलेंडर का कवर लोगों को पहली नज़र में ही आकर्षित करता है,वहीं अंदर की सामग्री को इस प्रकार सजाया गया है कि प्रत्येक तिथि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है,अतिथियों ने विशेष रूप से यह कहा कि कैलेंडर में तिथि अंकन अत्यंत साफ और स्पष्ट है,पूरे वर्ष की जानकारी एक नजर में समझ में आने योग्य है,कागज़ की गुणवत्ता मजबूत एवं टिकाऊ है,प्रिंटिंग, फिनिशिंग और लेआउट पूरी तरह प्रोफेशनल स्तर का है।

पंचायत से लेकर नगर निकाय प्रतिनिधियों की सहभागिता

जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा ने कहा कि ग्रामीण अंचलों की समस्याओं और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को सामने लाने में 'घटती घटना' की भूमिका सराहनीय रही है, उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े ने महिला सशक्तिकरण और समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को मंच देने वाली पत्रकारिता को ही सच्ची पत्रकारिता बताया, नगर पालिका उपाध्यक्ष आशीष यादव, नगर पंचायत पटना अध्यक्ष गायत्री सिंह एवं अन्य प्रतिनिधियों ने भी समाचार पत्र के जनपक्षधर रुख की प्रशंसा की।

पत्रकारिता के साथ उपयोगिता का संगम

दैनिक घटती-घटना द्वारा तैयार यह कैलेंडर इस बात का प्रमाण है कि समाचार पत्र केवल खबरों तक सीमित नहीं,बल्कि समाज की दैनिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर कार्य करता है,यह प्रयास पाठकों से जुड़े रहने और उन्हें उपयोगी सामग्री प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है।

पत्रकारिता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विमर्श

कैलेंडर विमोचन के पश्चात आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने पत्रकारिता की सामाजिक जिम्मेदारी,जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की। सभी ने एकमत से कहा कि सूचना के इस दौर में मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है,क्योंकि एक सजग और निष्पक्ष प्रेस ही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा कर सकता है। वर्ष 2026 के कैलेंडर का यह विमोचन कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि जनतंत्र,पत्रकारिता और सामाजिक उत्तरदायित्व का सामूहिक उत्सव बन गया। 'दैनिक घटती-घटना' ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि वह केवल समाचार पत्र नहीं, बल्कि जनता की आवाज और लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है।

लोकतांत्रिक मूल्यों की मिसाल बना आयोजन

स्थानीय रेस्ट हाउस,बैकुंठपुर में आयोजित इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एक मंच पर उपस्थित होकर निष्पक्ष पत्रकारिता के महत्व पर एकमत दिखाई दिए। मंच से यह स्पष्ट संदेश गया कि लोकतंत्र में मीडिया सत्ता का नहीं, बल्कि जनता का पक्षधर होता है।

वर्ष भर उपयोगी जानकारी से भरपूर

दैनिक घटती-घटना का यह वार्षिक कैलेंडर केवल तिथियों का संग्रह नहीं, बल्कि वर्ष भर मार्गदर्शन देने वाला सूचना-पत्र भी है,इसमें ऐसी सभी जानकारियों को सम्मिलित किया गया है, जो एक अच्छे कैलेंडर में होना आवश्यक होता है, ताकि आम नागरिक पूरे वर्ष इसका सहज उपयोग कर सके, कैलेंडर में सभी महीनों की पूर्ण तिथियां,प्रमुख धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्व,अवकाश संबंधी जानकारियां, महत्वपूर्ण दिवस,स्पष्ट दिनांक विन्यास को विशेष ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है।

कैलेंडर विमोचन पर जनप्रतिनिधियों,समाज सेवियों व पत्रकारों की प्रतिक्रियाएं... अतिथियों ने पत्रकारिता के धर्म पर रखे विचार

दैनिक घटती-घटना ने हमेशा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है,निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला है, कैलेंडर के साथ-साथ समाचार पत्र का यह प्रयास भी सराहनीय है। नए कैलेंडर के लिए मैं पूरे संस्थान को शुभकामनाएं देता हूँ।

श्याम बिहारी जायसवाल,स्वास्थ्य मंत्री

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुँचाने में 'घटती-घटना' की भूमिका प्रभावशाली रही है,यह कैलेंडर केवल तिथियों का संकलन नहीं,बल्कि जनसंघर्षों का प्रतीक है,नए कैलेंडर के लिए पूरे संस्थान को शुभकामनाएं देता हूँ।

भईयालाल राजवाड़े,विधायक

उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की सामाजिक जिम्मेदारी अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है,लेकिन 'घटती-घटना' ने अपनी क्रांतिकारी लेखनी से समाज में अलग पहचान बनाई है, नए कैलेंडर के लिए संस्थान को शुभकामनाएं।

गुलाब कमरो,पूर्व विधायक

उन्होंने कहा कि वही समाचार पत्र सशक्त कहलाता है जो सत्ता नहीं, बल्कि जनता की आवाज बने। इस आयोजन के माध्यम से मीडिया की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी दोनों पर सकारात्मक संदेश गया है।

देवेंद्र तिवारी,भाजपा जिलाध्यक्ष

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष,निर्भीक और जिम्मेदार पत्रकारिता अत्यंत आवश्यक है,घटती-घटना ने सदैव जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। सच के पक्ष में खड़े रहना आसान नहीं होता,लेकिन यह समाचार पत्र निरंतर उस दायित्व का निर्वहन करता आ रहा है, वर्ष 2026 के कैलेंडर विमोचन के इस अवसर पर मैं पूरे घटती-घटना परिवार को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ।

शैलेष शिवहरे,(पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बैकुण्ठपुर)

घटती-घटना ने सदैव सत्य और निष्पक्षता के साथ समाचारों का प्रकाशन किया है। यही इसकी पहचान है। इसकी धार आगे भी इसी तरह बुलंद रहे,यही शुभकामना है।

शैलेन्द्र सिंह,(कांग्रेस नेता)

जब पत्रकारिता अपने क्रांतिकारी स्वरूप में होती है,तभी वह समाज को सही दिशा दिखा पाती है। घटती-घटना ने हमेशा जनता के हितों की रक्षा की है।

योगेश शुक्ला,(वरिष्ठ कांग्रेस नेता)

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निष्पक्ष प्रेस अत्यंत आवश्यक है। हमें गर्व है कि बैकुंठपुर की धरती से ऐसा समाचार पत्र संचालित हो रहा है,जो सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखता है।

वेदांती तिवारी (वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व जिला पंचायत उपध्यक्ष)

लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को स्थान देना और जनता के संघर्षों को शब्द देना ही पत्रकारिता की वास्तविक सार्थकता है,घटती-घटना ने सदैव दबे-कुचले वर्ग की आवाज बनकर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। कैलेंडर विमोचन पर पूरे समाचार पत्र परिवार को बधाई।

अशोक जायसवाल (कांग्रेस नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बैकुंठपुर)

पत्रकारिता तभी सार्थक होती है जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करे, घटती-घटना अख़बार ने अपनी क्रांतिकारी लेखनी से हमेशा भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के खिलाफ शंखनाद किया है,जनहित के प्रति इसकी प्रतिबद्धता ही इसे अन्य समाचार पत्रों से अलग पहचान देती है। पूरे परिवार को सफल वर्ष के लिए शुभकामनाएं।

अनुराग दुबे,(गौ सेवक)

एक पत्रकार और प्रेस क्लब प्रतिनिधि के रूप में मैं गर्व से कह सकता हूं कि घटती-घटना अख़बार ने हमेशा पत्रकारिता के ऊँचे मापदंड स्थापित किए हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के पक्ष में खड़े रहना और सच को निडरता से लिखना ही इसकी असली पूंजी है, कैलेंडर विमोचन पर संपादक एवं पूरी टीम को हार्दिक बधाई।

कमलेश शर्मा,(अध्यक्ष,प्रेस क्लब कोरिया)

पत्रकारिता समाज का वह दर्पण है जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता। घटती-घटना अख़बार ने अपनी धारदार लेखनी से यह सिद्ध किया है कि जनहित सर्वोपरि है, यह आयोजन संस्थान की निरंतरता और सफलता का प्रतीक है। पूरे परिवार को उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं।

आशीष सोनी

शिक्षा और जागरूकता का गहरा संबंध है,घटती-घटना केवल समाचार नहीं देता, बल्कि समाज और युवाओं को जागरूक करने का कार्य भी कर रहा है। एक सजग मीडिया ही रोजगार और भविष्य से जुड़े मुद्दों को शासन तक प्रभावी रूप से पहुंचा सकता है।

राजकुमार साहू (संचालक,आईसेक्ट- सोनहत)

CMYK

धान नहीं तौला जाता...व्यवस्था नहीं चलती...नियम नहीं दिखते...यहां सिर्फ एक ही चीज भारी है... माफिया का वजन...

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र बना माफिया मंडी...

बिना हस्ताक्षर की शिकायत ने खोले कई राज, डाक से पहुंचा पत्र बना प्रशासन के लिए आईना...

प्रधानमंत्री से लेकर थाना प्रभारी तक को भेजी गई प्रतिलिपि, फिर भी सवाल वही ... कार्रवाई कब ?

धान माफिया का आतंकः शिवप्रसादनगर खरीदी केंद्र में हदीश मोहम्मद के खिलाफ सनसनीखेज शिकायत

एक सीजन में 20 करोड़ की हेराफेरी का दावा, शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में हदीश कटघरे में...

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में धान नहीं...घोटाला तौला गया ?

धान खरीदी घोटाले की जांच के घेरे में

शिवप्रसादनगर समिति से जुड़े ये नाम

- फर्जी तौल, फर्जी टोकन, करोड़ों की हेराफेरी के आरोप
- बीपीएल कार्ड, सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का दावा

धान खरीदी केंद्र बना कमाई का अड्डा! हदीश पर गंभीर आरोपों से सूरजपुर प्रशासन में हलचल

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र की जांच की मांग तेज,हदीश पर माफियागिरी और घोटाले के आरोप

बिना हस्ताक्षर की शिकायत ने मचाया प्रशासनिक हलचल,प्रधानमंत्री से लेकर जिला स्तर तक भेजी गई प्रतिलिपि

क्या हैं शिकायत में लगाए गए प्रमुख आरोप ?

1. तय मानक से अधिक धान की तौल

- शासन के अनुसार 40 किलो धान + बोरा मिलाकर 40.700 किलो वजन होना चाहिए।
- लेकिन केंद्र में किसानों से 41.700 किलो धान जबरन लिया जा रहा है।

2. हम्माली फंड का गबन

- शासन द्वारा मजदूरी के लिए फंड दिया जाता है।
- इसके बावजूद किसानों से 15 रुपये प्रति बोरा वसूले जाते हैं।
- आरोप है कि यह राशि हदीश मोहम्मद के निर्देश पर समिति प्रबंधक, खरीदी प्रभारी व कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच बांटी जाती है।

3. बिना धान जमा किए भुगतान

- सैकड़ों किसानों की ऋण पुस्तिका,बैंक पासबुक और चेकबुक हदीश के पास रहती है।
- रात में समिति में बैठकर बिना धान जमा किए ऑनलाइन एंट्री कराई जाती है।
- सहकारी बैंक भैयाथान से पैसा निकलवाकर आपस में बांटा जाता है।

4. फर्जी टोकन घोटाला

- टोकन केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जिनके दस्तावेज हदीश के पास होते हैं।
- शिकायत में दावा है कि 90 प्रतिशत टोकन बिना वास्तविक धान के काटे जाते हैं।

5. धान उठाव में भारी फर्जीवाड़ा

- बिना धान लोड किए ही ट्रकों का उठाव दर्शाया जाता है।
- एक ही धान लोडिंग की फोटो को कई बार उपयोग कर रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इससे हजारों क्विंटल धान का अंतर बताया गया है।

6. प्रतिदिन 10 लाख से अधिक की हेराफेरी

- शिकायत के अनुसार हदीश मोहम्मद द्वारा प्रतिदिन लगभग 10 लाख रुपये तक का
- भुगतान फर्जी तरीके से उठाया जाता है।
- एक सीजन में 10 से 20 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का दावा किया गया है।

7. धमकी,मारपीट और दहशत

- किसानों से जबरन ज्यादा धान भरवाया जाता है।
- मजदूरी न देने पर 40 रुपये प्रति क्विंटल वसूली।
- विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

8. अवैध संपत्ति का बड़ा खुलासा, शिकायत के अनुसार

पहले मात्र दो एकड़ जमीन रखने वाला हदीश आज- 50-60 एकड़ भूमि,दो ट्रैक्टर,दो जेसीबी,पिकअप वाहन,दो लग्जरी कार, लगभग 5 करोड़ का बंगला का मालिक है।

9. बीपीएल कार्ड व सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग

- हदीश, उसकी पत्नी,भाई,भाभी और मां के नाम पर तीन बीपीएल कार्ड धारक ।
- किसान सम्मान निधि,महतारी वंदन योजना और सैनिक स्कूल फीस छूट का लाभ लेने के आरोप।
- आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद गरीबों का हक छीने जाने का दावा।

10. खाद और राशन की कालाबाजारी

- सहकारी समिति में आने वाली खाद का बड़ा हिस्सा हदीश के
- निजी गोदाम में रखा जाता है। ऊंचे दामों पर बिक्री।
- बीपीएल चावल 20 रुपये किलो में खरीदकर शहरों में सप्लाई का आरोप।

किनके खिलाफ हैं आरोप-नाम सहित विवरण

शिकायत पत्र में निम्न व्यक्तियों के नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं...

- हदीश मोहम्मद-कथित मुख्य धान माफिया
- शोहराब-समिति प्रबंधक
- साधना कुशवाहा-धान खरीदी प्रभारी
- झम्मन साहू- कंप्यूटर ऑपरेटर
- चिरागु- सहकारी बैंक से राशि निकालने वाला व्यक्ति
- सदीक - हदीश का भाई
- महमूद- हदीश का ससुर

पत्र में आरोप है कि इन सभी की मिलीभगत से शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र को निजी कमाई का अड्डा बना दिया गया है।

प्रशासन के सामने बड़ा प्रश्न,अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि...

- क्या इस शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा ?
- क्या रिकॉर्ड का मिलान और ऑडिट जांच कराई जाएगी ?
- या यह पत्र भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दब जाएगा ?
- धान खरीदी शासन की सबसे संवेदनशील योजनाओं में से एक है...
- जिसका सीधा संबंध किसानों की आय और सरकारी खजाने से जुड़ा है।

निष्पक्ष जांच की उठ रही मांग

स्थानीय ग्रामीणों और किसान संगठनों का कहना है कि खरीदी रजिस्टर, बैंक भुगतान विवरण,टोकन कटौती,उठाव स्टॉक,परिवहन बिल की संयुक्त जांच कराई जाए,तभी सच्चाई सामने आ सकती है।

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,01 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ सरकार भले ही किसानों को अन्नदाता कहकर सम्मान देती हो,लेकिन सूरजपुर जिले का शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र यह बताने के लिए काफी है कि ज़मीनी हकीकत में अन्नदाता नहीं, बल्कि लुटने योग्य माल समझा जा रहा है, कलेक्टर कार्यालय से लेकर मीडिया दफ्तर तक पहुंचे लगातार शिकायती पत्रों,ग्रामीणों के बयानों और दस्तावेजों ने एक ऐसी तस्वीर सामने रख दी है,जो न केवल प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी पूछती है– क्या धान खरीदी केंद्र अब किसानों के लिए नहीं,माफियाओं के लिए खोले गए हैं?

बतादे की सूरजपुर जिले के चर्चित शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र को लेकर एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, डाक के माध्यम से दैनिक घटती-घटना कार्यालय को एक विस्तृत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है,जिसमें धान खरीदी व्यवस्था में कथित तौर पर हुए बड़े घोटाले का सिलसिलेवार उल्लेख किया गया है, यह शिकायत बिना हस्ताक्षर की है,

प्रधानमंत्री से लेकर थाना प्रभारी तक भेजी गई शिकायत

शिकायती पत्र में उल्लेख है कि इसकी प्रतिलिपि केवल मीडिया संस्थान को ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कृषि मंत्री, आयुक्त सरगुजा संभाग, पुलिस अधीक्षक सूरजपुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थाना प्रभारी कोतवाली सूरजपुर सहित अनेक उच्च जांच एजेंसियों को भी भेजी गई है, इससे यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए हर स्तर तक बात पहुंचाने का प्रयास किया है।

लेकिन इसमें दर्ज तथ्यों,नामों और कार्यप्रणाली ने पूरे जिले में खलबली मचा दी है,यह पत्र शुक्रवार को दैनिक घटती-घटना कार्यालय पहुंचा,जिसमें प्रार्थी के रूप में समस्त ग्रामीण लिखा गया है, हालांकि किसी व्यक्ति का नाम, पता अथवा हस्ताक्षर अंकित नहीं है,फिर भी शिकायत में जिस प्रकार धान खरीदी प्रक्रिया का सूक्ष्म विवरण दिया गया है,उसने मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है, बिना हस्ताक्षर के बावजूद शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र को लेकर सामने आई यह शिकायत सूरजपुर जिले की धान खरीदी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाती है,यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं,तो यह मामला जिले के सबसे बड़े धान खरीदी घोटालों में शामिल हो सकता है, अब देखना यह होगा कि प्रशासन जांच कर सच्चाई सामने लाता है या यह शिकायत भी कागजों में ही सिमट कर रह जाती है।

करोड़ों के संभावित घोटाले का दावा

शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख है कि पूरे एक खरीदी सीजन में,लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का कथित रूप से गबन किया जा रहा है,पत्र में यह दावा किया गया है कि यदि धान खरीदी केंद्र के रिकॉर्ड,बैंक भुगतान, टोकन कटौती और उठाव रजिस्टर की निष्पक्ष जांच कराई जाए,तो बड़े पैमाने पर अंतर सामने आ सकता है।

माफिया नेटवर्क के नामों का उल्लेख

शिकायत में कथित रूप से धान खरीदी केंद्र से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों, कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख किया गया है, आरोप है कि पूरा नेटवर्क संगठित रूप से कार्य कर रहा है, समिति प्रबंधन,कंप्यूटर ऑपरेटर व हम्माल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं,किसानों को धमकाकर चुप कराया जाता है,हालांकि दैनिक घटती-घटना इन नामों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है।

किसानों को डराने-धमकाने का आरोप

पत्र में यह भी कहा गया है कि जो किसान सवाल उठाते हैं, जिनकी तौल या भुगतान में गड़बड़ी होती है,उन्हें टोकन काटने,भुगतान रोकने अथवा भविष्य में धान न लेने की धमकी दी जाती है,इससे ग्रामीण किसान भय के कारण शिकायत करने से बचते हैं।

बिना हस्ताक्षर,फिर भी गंभीर सवाल

हालांकि यह शिकायत बिना हस्ताक्षर की है, लेकिन इसमें तारीखें, प्रक्रिया, अंदरूनी जानकारी,तकनीकी विवरण जिस प्रकार से दिए गए हैं,उससे यह सामान्य शिकायत प्रतीत नहीं होती,प्रशासनिक हलकों में भी यह चर्चा है कि इतनी बारीक जानकारी किसी अंदरूनी व्यक्ति को ही हो सकती है।

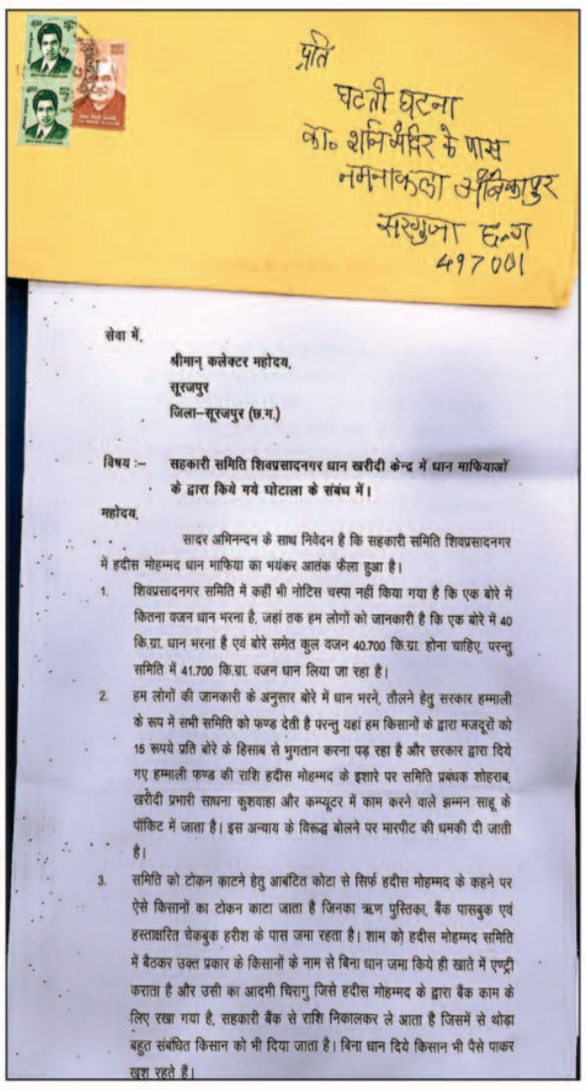

प्रति
घटती घटना
को० शनिमंदिर के पास
नमनाकला अम्बिकापुर
सरगुजा छ.ग.
497001

सेवा में,
श्रीमान् कलेक्टर महोदय,
सूरजपुर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– सहकारी समिति शिवप्रसादनगर धान खरीदी केन्द में धान माफियाओं के द्वारा किये गये घोटाला के संबंध में।

महोदय,

सादर अभिनन्दन के साथ निवेदन है कि सहकारी समिति शिवप्रसादनगर में हदीस मोहम्मद धान माफिया का भयंकर आतंक फैला हुआ है।

1. शिवप्रसादनगर समिति में कहीं भी नोटिस चस्पा नहीं किया गया है कि एक बोरे में कितना वजन धान भरना है, जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि एक बोरे में 40 कि.ग्रा. धान भरना है एवं बोरे समेत कुल वजन 40.700 कि.ग्रा. होना चाहिए, परन्तु समिति में 41.700 कि.ग्रा. वजन धान लिया जा रहा है।
2. हम लोगों की जानकारी के अनुसार बोरे में धान भरने, तौलने हेतु सरकार हम्माली के रूप में सभी समिति को फण्ड देती है परन्तु यहां हम किसानों के द्वारा मजदूरों को 15 रूपये प्रति बोरे के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है और सरकार द्वारा दिये गए हम्माली फण्ड की राशि हदीस मोहम्मद के इशारे पर समिति प्रबंधक शोहराब, खरीदी प्रभारी साधना कुशवाहा और कम्प्यूटर में काम करने वाले झम्मन साहू के पॉकिट में जाता है। इस अन्याय के विरूद्ध बोलने पर मारपीट की धमकी दी जाती है।
3. समिति को टोकन काटने हेतु आबंटित कोटा से सिर्फ हदीस मोहम्मद के कहने पर ऐसे किसानों का टोकन काटा जाता है जिनका ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक एवं हस्ताक्षरित चेकबुक हरीश के पास जमा रहता है। शाम को हदीस मोहम्मद समिति में बैठकर उक्त प्रकार के किसानों के नाम से बिना धान जमा किये ही खाते में एण्ट्री कराता है और उसी का आदमी चिरागु जिसे हदीस मोहम्मद के द्वारा बैंक काम के लिए रखा गया है, सहकारी बैंक से राशि निकालकर ले आता है जिसमें से थोड़ा बहुत संबंधित किसान को भी दिया जाता है। बिना धान दिये किसान भी पैसे पाकर खुश रहते हैं।

पहले भी उठ चुके हैं सवाल

गौरतलब है कि दैनिक घटती-घटना द्वारा शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र से जुड़ी अनियमितताओं पर पहले भी कई समाचार प्रकाशित किए जा चुके हैं,किसानों की शिकायतें,तौल विवाद और भुगतान संबंधी समस्याएं पूर्व में सामने आती रही हैं,अब यह शिकायती पत्र उन खबरों की पृष्ठभूमि में मामले को और गंभीर बना रहा है।

सबसे बड़ा सवाल – प्रशासन अब भी चुप क्यों ?

शिकायतें पहले भी हुईं, तारीखें भी हैं, दस्तावेज भी हैं,लेकिन–जांच नीचे भेजी गई,नीचे से ऊपर रिपोर्ट साफ-सुथरी आ गई,और माफिया और मजबूत हो गया,अब सवाल यह नहीं कि घोटाला हुआ या नहीं? सवाल यह है–घोटाले पर चुप्पी क्यों है?

बैंक भी गरीब के लिए गरीब,माफिया के लिए अमीर

आम किसान को बैंक कहता है एक दिन में 20 हजार से ज्यादा नहीं मिल सकता,लेकिन यहां माफिया के लिए कोई लिमिट नहीं,रोज लाखों रुपये निकलते हैं,रात में दुकान में बैठकर बंटवारा होता है प्रश्न यह नहीं कि पैसा निकला,प्रश्न यह है – बैंक ने पूछा क्यों नहीं – धान कहां है?

उठाव में सबसे बड़ा खेल – फोटो बोले, धान गायब

धान उठाव की कहानी और भी दिलचस्प है एक बार ट्रक में धान लोड, फोटो खींची गई, वही फोटो कई बार अपलोड कागजों में–हजारों क्विंटल धान उठा हकीकत में–गोदाम आधा खाली भी नहीं यानि–धान कागज पर चलता है,जमीन पर नहीं।

दैनिक घटती-घटना की अपील

सूरजपुर जिले के शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र से जुड़े मामले में यदि किसी भी व्यक्ति के पास दस्तावेज,प्रमाण,फोटो,वीडियो या अन्य ठोस जानकारी उपलब्ध है,तो वह दैनिक घटती-घटना कार्यालय, अंबिकापुर आकर जानकारी दे सकता है,सूत्र का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा,दैनिक घटती-घटना का प्रयास रहेगा कि खबरों के माध्यम से सरकार इस गंभीर मामले में संज्ञान ले,तथा धान खरीदी केंद्र में बड़े स्तर पर जांच कराई जाए,जिन व्यक्तियों पर आरोप हैं,उनके विरुद्ध स्वतंत्र जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठाई जाएगी।

जनहित में जारी...दैनिक घटती-घटना

जुआ संचालन और चावल तस्करी का आरोप

शिकायत पत्र में यह भी दावा किया गया है कि बीपीएल चावल 20 रुपये किलो में खरीदकर,पिकअप वाहन से सूरजपुर सप्लाई किया जाता है,दुकान के अंदर बने कमरे में बड़े जुआरियों को बैठाकर जुआ खेलाया जाता है।

पहले भी दी गई थी शिकायत

ग्रामीणों ने पत्र में उल्लेख किया है कि 16 अप्रैल 2025 को भी शिकायत की गई थी,जांच थाना प्रभारी को सौंपी गई, लेकिन कथित रूप से कार्रवाई नहीं हुई।

टोकन सिर्फ उन्हीं का,जिनकी पासबुक माफिया के पास

धान बेचने के लिए टोकन चाहिए,लेकिन टोकन सबको नहीं मिलता,टोकन सिर्फ उन्हें मिलता है जिनकी ऋण पुस्तिका,बैंक पासबुक,हस्ताक्षरित चेकबुक,पहले से माफिया के पास गिरवी पड़ी हो, शाम को बिना धान लाए, पोर्टल में एंट्री होती है,बैंक से पैसा निकलता है, थोड़ा किसान को मिलता है,बाकी व्यवस्था शुल्क बन जाता है धान नहींज्लेकिन भुगतान पूरा!

10 नहीं.. 20 करोड़ तक की काली खेती

शिकायतों में दावा है कि एक खरीदी सीजन में 15 से 20 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की जाती है, यदि पोर्टल रिकॉर्ड बैंक लेन-देन,मिलर भुगतान, उठाव रजिस्टर का ईमानदारी से मिलान हो जाए, तो घोटाले की फसल खुद सामने आ जाएगी।

किसान चुप क्यों हैं? क्योंकि डर जिंदा है

किसान सवाल नहीं करते, क्योंकि धमकी मिलती है,मारपीट होती है,धान न लेने की चेतावनी दी जाती है और खुलेआम कहा जाता है चौकी से लेकर ऊपर तक हिस्सा जाता है,मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता,यह सिर्फ धमकी नहीं,यह सिस्टम पर तमाचा है।

CMYK

रणवीर सिंह के हाथ एक और सफलता

नायक फेम डायरेक्टर की फिल्म में आएंगे नजर

रणवीर सिंह अपनी फिल्म धुरंधर की सफलता का आनंद ले रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर हिट रही। अब खबरें हैं कि वह निर्देशक शंकर की अपकमिंग फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह फिल्म शंकर का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो एक ऐतिहासिक उपन्यास पर आधारित है। रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। सिनेमाघरों में सक्सेसफुल टर्म के बाद मूवी 30 जनवरी को ओटीटी पर रिलीज हुई और छा गई। मिनटों में यूजर्स ने इसे देखकर सोशल मीडिया पर रिव्यू देना भी शुरू कर दिया।

अब धुरंधर में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करने के बाद एक्टर की झोली में एक और महत्वपूर्ण रोल आ गया है।

मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार,वे निर्देशक शंकर की मचअवेटेड फिल्म वेलपरी में नजर आ सकते हैं। इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है।

तमिल एक्टर के साथ आएंगे नजर

कहा जा रहा है कि फिल्म में दो हीरो होंगे और रणवीर सिंह के अलावा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता विक्रम भी वेलपरी में नजर आएंगे। कोलीवुड स्टार और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता इस तरह पहली बार साथ में नजर आएंगे।

माना जा रहा है कि वेलपरी निर्देशक शंकर का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। फैंस मूवी पर किसी ऑफिशियल अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सु.वेंकटेशन द्वारा लिखित तमिल भाषा के ऐतिहासिक उपन्यास वीरा युग नायकन वेलपरी पर आधारित यह फिल्म उन प्रशंसकों की दिलचस्पी जगाएगी जो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।

कब आएगा धुरंधर का दूसरा पार्ट?

वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ने 1300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च,2026 को रिलीज होगा।

देश की भाबीजी...टीवी एक्टर्स के लिए कैसे वरदान बनी धुरंधर

भाबीजी घर पर हैं फिल्म की कास्ट ने बताई सच्चाई

टीवी शो भाबीजी घर पर हैं ने फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया है। यह टेलीविजन पर काफी पॉपुलर शो है जिस पर अब भाबीजी घर पर हैं:- फन ऑन द रन फिल्म बनी है। हाल ही में फिल्म की टीम से बात की जिन्होंने बताया टीवी या फिल्म में से ज्यादा बेहतर क्या है? टीवी शो 'खिचड़ी' के बाद अब उसी कड़ी में एक और लोकप्रिय टीवी शो 'भाबीजी घर पर हैं' ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा है। फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं :- फन आन द रन' में शुभांगी अत्रे,आसिफ शेख और विदिशा श्रीवास्तव अपने-अपने चर्चित किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर लांच पर तीनों कलाकारों से स्मिता श्रीवास्तव की बातचीत के अंश...

इस बार सबसे ज्यादा फन क्या रहा ?

आसिफ :- सीमित समय की वजह से इस बार फन मोमेंट उतने नहीं रहे हैं। हां, चूंकि हम काम करते हुए ही एंज्वाय करते रहते हैं। सीन के रिहर्सल में ही मस्ती और इंप्रोवाइजेशन हो जाता है। यही वजह है कि आप ज्यादातर किरदारों से जुड़ाव पाएंगे। कहीं न कहीं ऐसे किरदार आपको समाज में मिल जाएंगे। इसमें निर्देशक शशांक बाली का बहुत योगदान रहा।

शुभांगी :- मैं एक मजेदार किस्सा बताती हूं। आपने फिल्म का पोस्टर देखा होगा, जिसमें हम सब गाड़ी में हैं। वो गाड़ी बहुत ही खटारा थी। पूरी फिल्म में मैंने उस गाड़ी को चलाया है। जब हम देहरादून पहुंचे तो सारे असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम थी। सब घबराए हुए थे। उन्होंने पूछा कि आपको गाड़ी चलानी आती है। मैंने बड़े आत्मविश्वास से हामी भर दी, फिर उन्होंने बताया कि इस गाड़ी को चलाना है। देहरादून पहुंचने के बाद उस रात एक घंटे गाड़ी के साथ मेरी ट्रेनिंग हुई। गाड़ी का ब्रेक भी सही से काम नहीं कर रहा था। उसके गेयर भी माशाअल्लाह थे। हां, गाड़ी को चलाने का अनुभव बहुत मजेदार था। उसके अलावा विभूति जी की एक सर्जरी मैं करती हूं, वो सीन भी शानदार था।

विदिशा:- फिल्म में मुझे सबसे ज्यादा मजा स्टंट करने में आया था। सूखी नदी के ऊपर ऊंचे ब्रिज से हार्नेस लगाकर स्टंट किया। मैंने बाडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। खुद करना चैलेंजिंग था,लेकिन बहुत रोमांचक भी। बाकी यह कॉमेडी फिल्म है तो फिल्म करते हुए हम इतनी कॉमेडी कर लेते हैं।

विदिशा :- मैं साउथ भारतीय फिल्मों में काम करने के बाद टीवी में आई। मैं बनारस से हूं, तारीफ कहीं भी हो जाए,लेकिन जब तब आपके अपने लोग नहीं पहचानेंगे,तब तक वो कमी खलती रहेगी। निश्चित रूप से इससे पहले भी मैंने धारावाहिक किए हैं, लेकिन हिंदी पट्टी में पहचान इस शो से ही मिली। एक बार एयरपोर्ट पर किसी ने मुझे भाबी जी बुलाया और मैं पलट गई। देश की भाबी जी बन गई हूं। मैं इसे अपने करियर की उपलब्धि मानती हूं।

शुभांगी:- इस शो की सबसे खूबसूरत बात यही रही कि हर हफ्ते कहानी बदलती थी, हर बार कुछ नया करने को मिलता था। 10 साल कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। एक कलाकार के तौर पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जब आप आपने काम को एंज्वाय कर रहे हों और हर वीक नया चैलेंज मिले तो बोरियत का सवाल नहीं होता। मैं अब नए किरदारों की ओर बढ़ रही हूं और जल्द ही दर्शकों को कुछ नया दिखेगा।

मैं इसे टॉप पर रखता हूं। मैं करीब 28 साल से काम कर रहा हूं। सवा सौ फिल्में प्रदर्शित हुईं। भारतीय टीवी का पहला डेली सोप 'हम लोग' से अभिनय का करियर शुरू किया था। उसके बाद ढेर सारी फिल्में भी कीं,लेकिन जो पॉपुलैरिटी इस शो से मिली,उसकी कोई तुलना नहीं है। यह हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कह सकते हैं कि इसके जरिए मेरे करियर का सबसे बेहतरीन समय चल रहा है। आर्थिक मजबूती के साथ लोकप्रियता, प्यार सब कुछ मिला,यह कंप्लीट पैकेज की तरह है। मैं उस स्टेज पर पहुंच गया था,जहां मुझे लगा था कि अब चाचा,ताऊ के रोल मिलेंगे। जब मैं हाथ बांधकर खड़ा रहूंगा और नए कलाकार एक्टिंग करेंगे। टीवी में यही होता है,लेकिन ईश्वर ने मुझे यह मौका दिया।

आसिफ:- मेरे हिसाब से यह लेबल मीडिया से आता है। मैं खुद को सिर्फ एक्टर मानता हूं। मैंने थिएटर किया है,सिनेमा किया है,टीवी भी किया है। टीवी एक्टर,फिल्म एक्टर,ए-लिस्टर जैसे ये टैग मुझे उतने जरूरी नहीं लगते हैं। एक्टर हमेशा एक्टर होता है।

शुभांगी :- ओरिजिनली से हम परफार्मर हैं। हम आर्टिस्ट हैं। हमारे काम के माध्यम अलग हो सकते हैं, लेकिन काम की शिद्दत वही रहती है। एक्टर को खुला आसमान देना चाहिए। वैसे अब समय बदल रहा है। लोग अलग-अलग भूमिकाओं में कलाकारों को स्वीकार रहे हैं। यह बदलाव अच्छा है।

आसिफ:- अब जैसे फिल्म 'धुरंधर' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें कितने सारे टीवी कलाकारों ने काम किया हैं। राकेश बेदी हैं, गौरव गेरा हैं,सौम्या टंडन हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि टीवी एक्टर्स बहुत मेहनती होते हैं। मेरे हिसाब से टीवी एक्टर बुलाना किसी कलाकार को कमतर आंकना है या सीमित कर देना है।

कंफ्यूजन के दलदल में फंसी भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर

भूमि पेडनेकर की डार्क क्राइम थ्रिलर दलदल अमेजन प्राइम वीडियो पर 30 जनवरी को रिलीज हुई। फिल्म एक सीरीयल किलर और भूमि पेडनेकर के किरदार एसीपी रीता फरेरा किरदार के इर्दगिर्द घूमती है। आइए जानते हैं इस रिव्यू में कैसी है क्राइम थ्रिलर सीरीज? भूमि पेडनेकर की डार्क क्राइम-थ्रिलर दलदल एक इन्वेस्टिगेशन के बीच सामाजिक सच्चाइयों को दिखाती है। भूमि पेडनेकर स्टारर यह क्राइम थ्रिलर साइकोलॉजिकल सिचुएशन, दिल दहला देने वाले मर्डर और सस्पेंस से भरी है।

क्या है सीरीज की कहानी?

डायरेक्टर अमृत राज गुप्ता की क्राइम-थ्रिलर सीरीज़ दलदल मुंबई की नई-नई बनी एसीपी रीटा फरेरा (भूमि पेडनेकर) के संघर्षों को दिखाती है,जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और अपने अतीत के पछतावे के बीच फंसी हुई है। रीटा एक ऐसी जांच शुरू करती है जो उसे एक बेरहम सीरियल किलर के सामने ले आती है,जबकि वह मीडिया ट्रायल से भी जूझ रही होती है। यह शो पुलिस अधिकारियों की अंदरूनी दुनिया को दिखाता है जो शहर को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हुए अपनी पर्सनल और पारिवारिक मुश्किलों को भी संभालते हैं। दलदल जेंडर-बेस्ड अपराधों,बच्चों के साथ दर्व्यवहार,ह्यूमन ट्रैफिकिंग,टॉक्सिक पेरेंटिंग और वर्कप्लेस सेक्सिज्म से जुड़े कई मुद्दों को एक साथ छूती है।

दलदल वेब सीरीज रिव्यू

दलदल की कहानी की सबसे खास बात यह कि इसमें साइकोलॉजी और क्राइम का मिक्सचर है,जो दिखाता है कि बचपन में झेला गया ट्रॉमा किस तरह एक क्रिमिनल माइंड को जन्म देता है। सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है भूमि पेडनेकर के किरदार रिटा फरेरा की एक रेड से जिसमें वे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी कई लड़कियों को बचाती है। इस केस को सॉल्व करने के बाद उसे प्रमोशन मिल जाता है और वह डीसीपी बन जाती है। डीसीपी बनते ही पहला केस आता है मर्डर आता और ये कोई मामूली केस नहीं बल्कि सीरीयल मर्डर केस है जिसमें सीरीयल किलर एक ही तरीके से अलग-अलग लोगों को मारता है। हालांकि मर्डर होने से पहले रिटा की जिंदगी के कुछ फ्लैशबेक दिखाए जाते हैं जिनमें वह मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होती है और सामने वाले इंसान का मर्डर करना चाहती है, जो कि काफी कंफ्यूजिंग भी लगता है।ह्यूमन ट्रेफिकिंग के साथ शुरू हुई इस कहानी में आगे जाकर सीरियल मर्डर्स,पितृसत्ता जैसे मुद्दों को भी उठाया गया है। इतने सारे अपराधों के साथ सीरीज को दिलचस्प बनाना थोड़ा कठिन काम तो है। इसीलिए बीच-बीच सीरीज थोड़ी धीमी और बोरिंग हो जाती है। कहानी में कंफ्यूजन आ जाता है और क्लामैक्स से पहले ही थकावट महसूस होती है।

खेल समाचार

भारत अंडर-19 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंचा

253 रन का टारगेट 33.3 ओवर में चेज नहीं कर सका पाकिस्तान उस्मान फिफ्टी लगाकर आउट

बुलवायो,01 फरवरी 2026। भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। पाकिस्तान को नॉकआउट में पहुंचने के लिए 253 रन का टारगेट 33.3 ओवर में हासिल करना था। टीम 167 तक ही पहुंच सकी। अब मैच जीतकर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर ही रहेगा। बुलवायो में रविवार को पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 252 रन बनाए थे।

पाकिस्तान ने 36 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 169 रन बना लिए हैं। अल हसन बलोच (2 रन) और हुजैफा अहसान (1 रन) पिच पर मौजूद हैं। आयुष म्हात्रे ने फिफ्टी लगाने वाले उस्मान खान को एलबीडब्ल्यू किया। उन्होंने अहमद हुसैन को भी पवेलियन भेजा।

कप्तान फरहान यूसुफ 38 रन बनाकर आउट हुए,उन्हें आरएस अम्ब्रिश ने कैच कराया। हमजा जहूर 42 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें कनिष्क चौहान ने बोल्ड किया। हेनिल पटेल ने समीर मिन्हास को चौथे ओवर में एलबीडब्ल्यू कर दिया। वे 9 रन बनाकर आउट हुए। समीर ने ही एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ 172 रन बनाए थे।

वेदांत ने फिफ्टी लगाई

वेदांत त्रिवेदी ने 68 रन बनाकर टीम को 200 के करीब पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंद पर 30 रन ही बना सके। कप्तान आयुष म्हात्रे खाता भी नहीं खोल पाए। आखिर में कनिष्क चौहान और खिलन पटेल ने फिफ्टी पार्टनरशिप कर स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। पाकिस्तान से अब्दुल सुभान ने 3 और मोहम्मद सय्याम ने 2 विकेट लिए।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत:- आयुष म्हात्रे (कप्तान), आरोन जॉर्ज,वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा,अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर),वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंब्रिश,कनिष्क चौहान, खिलन पटेल,हेनिल पटेल और दीपेश देवेन्द्रन।

पाकिस्तान:- फरहान यूसुफ (कप्तान),हमजा जहूर,समीर मिन्हास, उस्मान खान,अहमद हुसैन, हुजैफा अहसन,अली हसन,अब्दुल सुभान, मोमिन कमर,मोहम्मद सय्याम,और अली रजा।

अल्काराज ने अपने पहले करियर ग्रैंडस्लैम के साथ इतिहास रचा

मेलबोर्न,01 फरवरी 2026। पुरुषों के टेनिस में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे कार्लोस अल्काराज़ ने एक और उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर करियर ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रच दिया। स्पेन के इस खिलाड़ी ने 22 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल किया। अल्काराज़ ने 88 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और पुरुषों के टेनिस के इतिहास में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। टेनिस में नए उत्तराधिकारी कार्लोस अल्काराज़ एक बार फिर छा गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल जीतकर अपने कड़े प्रतिद्वंद्वी नोवाक जोकोविच के 25वें ग्रैंड स्लैम के सपने को तोड़ दिया। एक रोमांचक मैच में पहला सेट हारने के बावजूद,अल्काराज़ ने चार सेट के मुकाबले में जोकोविच को चौंका दिया। अनुभवी जोकोविच पर हावी रहे स्पेन के इस खिलाड़ी ने 2-6 6-2 6-3 7-5 से जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। इसके साथ ही, अल्काराज़ ओपन एरा में यह उपलब्धि हासिल करने वाले छठे खिलाड़ी बन गए। नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी ने 22 साल और 277 दिन की उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम का सपना पूरा किया। 1962 में रॉड लेवर द्वारा 24 साल और 32 दिन की उम्र में बनाया गया रिकॉर्ड टूट गया।

पुरुषों के टेनिस ओपन एरा में, अल्काराज़ से पहले छह पुरुषों ने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था। रॉड लेवर, आंद्रे अगासी और नोवाक जोकोविच ने यह उपलब्धि एक-एक बार हासिल की, और राफेल नडाल ने इसे दो बार हासिल किया। कार्लोस अल्काराज़ 22 साल 272 दिन रॉड लेवर 24 साल 32 दिन राफेल नडाल 24 साल 102 दिन राफेल नडाल 27 साल 303 दिन नोवाक जोकोविच 29 साल 15 दिन आंद्रे अगासी 29 साल 68 दिन

कर्नाटक और झारखंड के साथ इन टीमों ने किया क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई

नई दिल्ली,01 फरवरी 2026। कर्नाटक,झारखंड,आंध्र,उत्तराखंड के साथ जम्मू और कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में, कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने 85 गेंदों में नाबाद 120 रन बनाकर पंजाब के खिलाफ सिर्फ 27.5 ओवर में 250 रनों का शानदार लक्ष्य हासिल किया। इसी के साथ टीम ने आखिरी क्वार्टर-फाइनल स्पॉट अपने नाम किया। चंडीगढ़ को पारी और 56 रन से मात देने वाली सौराष्ट्र की टीम, मध्य प्रदेश की जगह पक्की करने के बाद एलीट ग्रुप बी से आखिरी क्वार्टर-फाइनल बर्थ हासिल करने के लिए तैयार दिख रही थी, लेकिन उनकी उम्मीदें इस बात पर टिकी थीं कि कर्नाटक मोहाली में जीत न पाए, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने सौराष्ट्र की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।एलीट ग्रुप ए में झारखंड,आंध्र और विदर्भ 31-31 अंकों के साथ टॉप पर थे, लेकिन बोनस प्वाइंट की जीत ने उन्हें अलग कर दिया। झारखंड और आंध्र ने अगले दौर में जगह बनाई, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन विदर्भ सिर्फ एक प्वाइंट के साथ बाहर हो गया। भले ही विदर्भ ने उत्तर प्रदेश को 4 विकेट से हराया, लेकिन ये टीम बहुत कम अंतर से नॉकआउट में जगह बनाने से चूक गई। अब फैंस को इस सीजन में एक नया रणजी ट्रॉफी चैंपियन मिलेगा। एलीट ग्रुप सी की बात करें तो,बंगाल ने हरियाणा को हराते हुए टेबल-टॉपर बनकर रोहतक में नॉकआउट में जगह बनाई, उसके बाद उत्तराखंड ने असम को पारी और 42 रनों से हराकर क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई। एलीट ग्रुप डी में, मुंबई को दिल्ली के खिलाफ ड्रॉ खेलने पर मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर ने दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम के तौर पर नॉकआउट में जगह पक्की कर ली। रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल 1 में झारखंड का सामना उत्तराखंड से होगा, जबकि क्वार्टर फाइनल 2 में मध्य प्रदेश के सामने जम्मू और कश्मीर की टीम होगी। क्वार्टर फाइनल 3 में बंगाल का सामना आंध्र से होगा। क्वार्टर फाइनल 4 में मुंबई और कर्नाटक के बीच मुकाबला खेला जाना है।

आदित्य-वीरेंद्र ने हाइलैंड्स रैली जीती

डीन-गगन ने पहला आईएनआरसी खिताब जीता

इंदौर,01 फरवरी 2026। कर्नाटक के डीन मस्कारेनहास और अनुभवी को-ड्राइवर गगन करुंबैया ने एक राउंड बाकी रहते हुए अपना पहला इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप खिताब पक्का कर लिया,जबकि हिमाचल प्रदेश के उनके टीएसआई रेसिंग टीम के साथी आदित्य ठाकुर और वीरेंद्र कश्यप ने रविवार को नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक्स पीथमपुर में आयोजित 2025 सीज़न के पांचवें और अंतिम से पहले राउंड, रैली ऑफ़ द हाइलैंड्स में ओवरऑल सम्मान हासिल किया। डीन और गगन फाइनल दिन

ओवरऑल पांचवें स्थान पर रहे, जिससे उन्हें एक महत्वपूर्ण चैंपियनशिप पॉइंट मिला जिसने उन्हें एक अजेय अस्थायी बढ़त दी और उनके पहले नेशनल खिताब की पुष्टि की। डीन,जिन्होंने 2010 में के1000 में रैली में डेब्यू किया था, 2019 में सिर्फ एक पॉइंट से चैंपियनशिप जीतने से चूक गए थे। अविश्वसनीय। आखिरकार ओवर ऑल नेशनल चैंपियनशिप जीतना एक अद्भुत एहसास है, मस्कारेनहास ने कहा। मैंने इस पल के लिए 15 साल से ज़्यादा इंतज़ार किया है। टीएसआई रेसिंग और पीएच स्पोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिनके बिना यह संभव नहीं होता। मैं विशेष रूप से अपने को-ड्राइवर,गगन का आभारी हूँ,जो शानदार रहे हैं। यह मेरे करियर में सच में एक यादगार मील का पत्थर है। यह जोड़ी 2019 में कोयंबटूर रैली से एक-दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रही है। मामूली मैकेनिकल दिक्कतों के बावजूद, आदित्य ठाकुर और वीरेंद्र कश्यप ने रैली जीतने के लिए संयमित ड्राइव किया। आज पहले स्टेज में हमारा गियर माउंटिंग टूट गया था,लेकिन हम स्टेज पूरा करने में कामयाब रहे। उसके बाद आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था,इसलिए हमने अपनी स्थिति बनाए रखने और कार को सुरक्षित घर लाने पर ध्यान केंद्रित किया,ठाकुर ने कहा। इस कार को चलाना खुशी की बात है, और हमें टीम के लिए अपनी पहली जीत हासिल करके खुशी हो रही है। चैंपियनशिप जीतने पर डीन को बधाई। डिफेंडिंग चैंपियन कर्ण कड़ूर, जिनके पार्टनर मूसा शरीफ थे,ने फाइनल दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहे।

दूसरे दिन युवा खिलाड़ियों ने दिखाई दमदार प्रदर्शन

चेन्नई ,01 फरवरी 2026। ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप -15 टेबल टेनिस के दूसरे दिन, टीएनपीईएसयू चेन्नई में लीग स्टेज में मुकाबले तेज़ हो गए, जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों कैटेगरी के खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त सीधे गेम में जीत और कड़े मुकाबले वाले पांच-सेट के मैच खेले,जिससे ग्रूप स्टैंडिंग बनने लगी,जैसा कि एक रिलीज़ में बताया गया है। लड़कों की कैटेगरी में,आदित्य ने कुमार हार्दिक पर सीधे गेम में जीत (3-0) के साथ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा,जबकि भट्ट देव ने एक

करीबी पांच-सेट के मैच में आचार्य आरव को हराया (3-2)। राजवेलु आकाश ने दत्ता अरिव के खिलाफ 3-0 से जीत के साथ अपना दबदबा बनाए रखा, और बुचुपल्ली हासित ने पाटिल विरेन (3-0) और विवान खन्ना (3-1) पर जीत के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। जना रुद्रनील ने भी सिनाई कैरो चंदन और साहनी आरव के खिलाफ सीधे गेम में शांत जीत के साथ प्रभावित किया, जबकि सेनगुप्ता सोमदेव ने दो अहम जीत दर्ज कीं,जिसमें उन्होंने चक्रवर्ती देबांशी (3-0) और गोसर अहान (3-1) को हराया। दिन का मुख्य आकर्षण ग्रूप एफ में आया,जहाँ बनर्जी सौस्वर्या ने एक रोमांचक पांच-सेट की लड़ाई में डुकलान वत्सल को हराया, और निर्णायक सेट 20-18 से जीता।

महिला टी 20 वर्ल्ड कप के लिए टीमें फाइनल : स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्वालीफाई कर गए

क्वींसलैंड,01 फरवरी 2026। विमेंस टी 20 वर्ल्ड कप की जगहें फाइनल हो गई हैं। क्वालिफायर में अपना दम दिखाने वाले स्कॉटलैंड ने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उन्होंने सुपर सिक्स मैच में यूनाइटेड स्टेट्स को हराकर अहम पॉइंट्स हासिल किए। स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप रिंग में उतरने वाली आखिरी टीम बनी। आयरलैंड, जिसने पहले एक और मैच में थाईलैंड को हराया था,ने वर्ल्ड कप की जगह पक्की कर ली है। विमेंस टी 20 वर्ल्ड कप इस साल जून और जुलाई के बीच इंग्लैंड और वेल्स में होगा। इस बार वर्ल्ड कप के लिए कुल 12 टीमें मुकाबला करेंगी। पिछले सीजन में टॉप-5 में रहने वाली इंग्लैंड,ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड,साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने क्वालीफाई

कर लिया है। श्रीलंका और पाकिस्तान ने रैंकिंग के आधार पर जगह पक्की कर ली है,जबकि बांग्लादेश, आयरलैंड, नामीबिया और स्कॉटलैंड ने ग्लोबल क्वालिफायर के आधार पर टी 20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। स्कॉटलैंड ने अचानक हुए बदलावों के बीच पुरुषों के टी 20 वर्ल्ड कप में एंट्री की। क्वालिफायर में यूएसए को हराने वाली विमेंस टीम ने जगह पक्की कर ली है।

केंद्रीय बजट 2026-27 पर मुख्यमंत्री साय की प्रतिक्रिया....

यह बजट विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम : सीएम साय

रायपुर,01 फरवरी 2026।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में बना हुआ यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख कर्तव्यों-आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि,जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा 'सबका साथ, सबका विकास' को केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब,किसान,युवा,महिला,मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इस बजट का सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती...

बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने,पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर...

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। स्टार्टअप,एमएसएमई,मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई भी पहले की तुलना में सस्ती होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल...

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन,हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना,मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

बेहतर कनेक्टिविटी के अवसर मिलेंगे : अमर अग्रवाल

पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं,बल्कि सरकार का ठोस और दूरदर्शी संकल्प है। बीते 12 वर्षों में देश की आर्थिक यात्रा वित्तीय अनुशासन,नियंत्रित महंगाई और औसतन 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा कि निवेश,उद्योग और रोजगार सृजन,पब्लिक इन्वेस्टमेंट और मजबूत वित्तीय प्रणाली पर विशेष जोर से छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन-समृद्ध राज्य को औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।

महिला सशक्तिकरण को नई दिशा

लखपति दीदी योजना के विस्तार के माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से उन्हें उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी।

उद्योग, शिक्षा और खेल को बढ़ावा

देश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर,20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। वहीं खेलो इंडिया मिशन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से बच्चों और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।

साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आयकर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और छोटे करदाताओं के लिए आसान व्यवस्था की गई है। दवाइयां,कपड़े, जूते,मोबाइल,ईवी बैटरी,सोलर उपकरण, बायोगैस-सीएनजी सहित कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी,जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' की भावना को और मजबूत करता है। यह बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा।

विकसित भारत की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक बजट : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए इसे 'विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट' बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट आम नागरिक के जीवन को सरल और सुगम बनाने वाला है,जिसमें देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग की जरूरतों को धरातल पर जाकर समझते हुए प्रावधान किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को यह बजट और मजबूती देता है।

बजट प्रतिक्रिया

शराब-महंगी...मछली-सस्ती,छत्तीसगढ़ को बजट में कुछ नहीं मिला : भूपेश

भूपेश बघेल बोले ने मीडिया से बयान में बजट पर कहा कि ना कृषि क्षेत्र में, ना उद्योग क्षेत्र में,ना रोजगार मजदूरों के क्षेत्र में कुछ ऐलान हुआ। यही कारण है कि शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गिरा। बहुत निराशाजनक बजट है। सेलेब को जस के तस रखा गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए बजट में कोई नहीं ऐलान होने पर बघेल ने सराकर पर तंज किया। कहा कि छत्तीसगढ़ को अडानी के लिए छोड़ दिया गया। उनके लिए जगह रखा गया है। प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ा दी गई है। अब शराब महंगी कर दी गई। इससे अवैध शराब की बिक्री बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ को ठगने का किया काम : दीपक बैज

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ को ठगने का काम किया गया है। मोदी सरकार का बजट आते ही शेयर मार्केट गिर गया,क्योंकि ना ही महंगाई कम हुई और ना ही गरीब आदमी को कुछ मिला। इस बजट में क्षेत्रीय असमानता बहुत है। जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है,वहां चुनावी लाभ लेने उपकृत करने का काम मोदी सरकार ने किया है। बैज ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झूठ बोलने का काम किया है। इस बजट ने किसानों को ठगने का काम किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए,एक्ससाइज ड्यूटी नहीं घटाई। पिछले साल भी कहा था कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इस बार भी यही कहा।

इस बजट में बढ़ा कैपेक्स विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह

विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 9वीं बार बजट पेश करने को ऐतिहासिक अवसर बताया। रविवार को देश में दूसरी बार बजट पेश हुआ। पहली बार 1999 में एनडीए सरकार में मंत्री यशवंत सिन्हां ने बजट किया था, जिसके बाद आज दूसरी बार ऐसा अवसर आया। पीएम मोदी के विजन 2047 की दिशा और भारत के लोगों के विकास की दृष्टि से यह दूर्शी बजट है। अधोसंरचना और विकास के संबंध में देश के लिए बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। बजट के प्रमुख तीन बिंदुओ पर फोक्स रहा। इस बजट में कैपेक्स 11 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को मजबूती मिलेगी।

'विकसित भारत' के साथ खुशहाल छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव : सांसद बृजमोहन अग्रवाल

सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने वाला और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए ऐतिहासिक बजट बताया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक मंदी और अस्थिरता के दौर में भी देश की विकास दर को 7 प्रतिशत पर बनाए रखना मोदी सरकार की मजबूत आर्थिक नीति और दूरदर्शिता का प्रमाण है। यह बजट युवा, महिला सशक्तिकरण,रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में 12.2 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जिससे देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ को इसका सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़,ओडिशा और केरल में माइनिंग कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इससे कोयला,लौह अयस्क और बॉक्साइट क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी,परिवहन लागत घटेगी और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य वेधशालाओं की स्थापना और जनजातीय स्कूलों में स्पोर्ट्स हब विकसित करने का प्रस्ताव सामाजिक विकास को नई दिशा देगा।

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 'बंद' न्यायधानी में बेअसर

सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों ने जताया रोष

बिलासपुर,01 फरवरी 2026।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरोध में आज देशभर में सवर्ण समाज ने बंद का आह्वान किया है। हालांकि, छत्तीसगढ़ की न्याय धानी बिलासपुर में बंद बेअसर नजर आया और मुख्य बाजार सामान्य दिनों की तरह खुले रहे। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है, विभिन्न संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। सामान्य वर्ग के समाज प्रतिनिधियों, शिक्षकों,छात्रों और विभिन्न संगठनों ने यूजीसी के नए नियमों पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के हितों के खिलाफ है। सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों की अनदेखी की जा रही है। यूजीसी कानून विरोध आंदोलन के संयोजक डॉ प्रदीप शुक्ला ने कहा कि जब तक इन नियमों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज शहर में बड़ी रैली निकालने और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।

क्यों हो रहा यूजीसी के नियमों का विरोध : बता दें, यूजीसी ने यह नियम रोहित वेमुला और पायल तड़वी की कथित जातिगत भेदभाव के कारण हुए हत्या मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार किए थे,ताकि कैंपस में जातिगत और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन नियम लागू होते ही देशभर में सवर्ण समाज ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर लगाई रोक

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए कहा कि 'भेदभाव' की परिभाषा वर्तमान रेगुलेशन में बहुत धुंधली है।नियमों को और अधिक समावेशी बनाने की जरूरत है ताकि यह देखा जा सके कि ये 'समानता के अधिकार' का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता, 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही प्रभावी रहेंगे।

विवाद की मुख्य वजहें और विरोधियों के तर्क

ओबीसी को शामिल करना : विरोधियों का तर्क है कि एससी-एसटी के साथ अब ओबीसी को भी इन कड़े सुरक्षा प्रावधानों में शामिल करना नियमों के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाता है।

झूठे आरोपों का डर : सवर्ण संगठनों का मानना है कि 'इक्विटी स्क्वाड' और 'समता दूत' जैसी व्यवस्थाओं से निर्दोष छात्रों और शिक्षकों को आपसी रंजिश के चलते झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है।

असमान सुरक्षा : तर्क दिया जा रहा है कि नियम केवल आरक्षित वर्गों की सुरक्षा की बात करते हैं।

रायपुर में ई-सिगरेट, हुक्का-तंबाकू का जखीरा जब्त

ट्रांसपोर्टर के ठिकाने पर पुलिस की रेड,25 लाख का माल बरामद,गोदाम मैनेजर गिरफ्तार

रायपुर,01 फरवरी 2026।
रायपुर में पुलिस ने न्यू गोंदवारा बस्ती स्थित एक गोदाम से प्रतिबंधित ई-सिगरेट,फ्लेवर तंबाखू और हुक्का पॉट का जखीरा बरामद किया है। जब्त सामान की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गोदाम के मैनेजर प्रबोध शर्मा गिरफ्तार किया गया। पुलिस फरार मालिकों की तलाश कर रही है। यह कार्रवाई खमतराई और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने की है।

क्या है पूरा मामला : एसीसीयू के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी, कि खमतराई थानाक्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की खेप एक गोदाम में रखी है। मुखबिर की सूचना पर एसीसीयू-खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम ने गोदाम में दबिश दी। अफसरों ने देर रात ट्रांसपोर्टर को बुलाकर गोदाम खुलवाया और सामान को जब्त करने की कार्रवाई की है।

ये सामान हुआ जब्त

गोदाम की तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में कार्टूनों में पैक ई-सिगरेट डिवाइस, फ्लेवर युक्त लिक्विड, हुक्का तंबाकू और अन्य सामग्री बरामद की गई।

दूसरे राज्यों से आता था माल

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रांसपोर्टर और गोदाम से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह माल दूसरे राज्यों से ट्रांसपोर्ट के जरिए रायपुर लाया गया था और यहां से शहर के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं।

वाहन चेकिंग में कार से मिला 8 लाख मूल्य का 15 किलो गांजा

तीन अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार...

कवर्धा,01 फरवरी 2026। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिल्फी थाना क्षेत्र से तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान कार से 15.480 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 7.75 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने मौके से वाहन और मोबाइल फोन समेत कुल 12.95 लाख रुपए की सामग्री जब्त की है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर रायपुर होते हुए उत्तरप्रदेश सप्लाई करते थे। गांजा को छोटी पुड़ियों में बेचकर अवैध मुनाफा कमाया जाता था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है।

यूथ कांग्रेस ने लॉलीपॉप बांटकर किया बजट का विरोध

जयस्तंभ चौक पर भाजपा मंत्रियों का मुखौटा पहनकर की भाजपा के खिलाफ नारेबाजी

रायपुर,01 फरवरी 2026।
केंद्रीय बजट को लेकर युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। जयस्तंभ चौक पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम जनता को लॉलीपॉप बांटकर केंद्र सरकार के बजट का विरोध जताया। युवा कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है। न तो आम जनता के लिए कोई ठोस प्रावधान किया गया और न ही युवाओं के लिए रोजगार या विकास से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं का मुखौटा पहनकर नारे लगाए,'छत्तीसगढ़ के युवाओं को लॉलीपॉप देना बंद करो 'और 'बजट के नाम पर छलावा नहीं चलेगा। आकाश शर्मा ने कहा कि संसद में पेश किया गया बजट छत्तीसगढ़ और यहां के युवाओं के लिए पूरी तरह निराशाजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से भारी राजस्व वसूलती है, लेकिन बदले में राज्य को न तो प्राथमिकता दी जाती है और न ही रोजगार से जुड़ी कोई बड़ी योजना दी जाती है।

सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी...नक्सलियों का विशाल डंप बरामद,प्रेशर कुकर आईईडी नष्ट

नारायणपुर,01 फरवरी 2026। घोर नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारायणपुर पुलिस, डीआरजी और 53 वीं वाहिनी आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का एक विशाल डंप बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान आईटीबीपी की बीडीएस (बम डिस्पोजल स्क्वॉड) टीम ने सर्च के दौरान मिले प्रेशर कुकर आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट किया, जिससे किसी बड़ी घटना को टाल दिया गया। जानकारी के अनुसार,यह संयुक्त सर्च ऑपरेशन ग्राम मडोड़ा से भोटोर के बीच घने और दुर्गम जंगलों में चलाया गया। यह इलाका लंबे समय से नक्सलियों की गतिविधियों और मूवमेंट के लिए जाना जाता रहा है। सुरक्षा बलों को पहले से ही इस क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी और उनके ठहरने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन की योजना बनाई गई। सर्चिंग के दौरान जंगल के भीतर जमीन में छिपाकर रखा गया नक्सलियों का डंप बरामद किया गया। डंप से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग का सामान मिला है। बरामद सामग्री में बड़ी संख्या में डेटोनेटर, ड्रम, राशन सामग्री, बर्तन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि नक्सली इस डंप का उपयोग लंबे समय तक जंगल में ठहरने और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश के तहत कर रहे थे। सबसे गंभीर बात यह रही कि सर्च के दौरान एक प्रेशर कुकर आईईडी भी मिला, जिसे नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। आईटीबीपी की बीडीएस टीम ने अत्यंत सावधानी बरतते हुए आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। समय रहते आईईडी के निष्क्रिय होने से सुरक्षा बलों और आसपास के क्षेत्र को बड़े खतरे से बचा लिया गया। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है और उनके लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी गहरा झटका लगा है। बरामद सामग्री की विस्तृत जांच की जा रही है,ताकि नक्सलियों के मूवमेंट, सप्लाई रूट और नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई जा सकें। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है और आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने साफ किया है कि नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए ऐसे ऑपरेशन आगे भी किए जाएंगे।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)